लखनऊ
बुधवार, 15 जुलाई, 2026
वर्ष : 11 । अंक: 317
मूल्य : 1 रुपये
पृष्ठ : 8
UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक आर्यावर्त क्रांति

पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे, तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सीखा देती है।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi
NIGHT 28° Low

संक्षेप

महुआ मोइत्रा, उद्धव ठाकरे की सोनम वांगचुक से अपील, बोले- सरकार को आपकी परवाह नहीं, अनशन छोड़ें

नई दिल्ली। मंगलवार को क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने की मांगें बढ़ गईं, क्योंकि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके ने उनकी सेहत के बारे में जानकारी दी। दिपके ने X पर बताया कि वांगचुक के शरीर की मांसपेशियां कम होने लगी हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। CJP के फ़ाउंडर ने बताया कि वांगचुक का वज़न 8.5 किलो कम हो गया है और उनका ब्लड प्रेशर 109/70 है। दिपके ने वांगचुक के साथ हुई अपनी एक छोटी सी बातचीत का ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की गुज़ारिश की थी। उनके शरीर की मांसपेशियां कम होने लगी हैं और उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। बाकी लोगों की तरह, मैंने भी उनसे अपना अनशन खत्म करने की विनती की। उन्होंने शांति से जवाब दिया कि मुझसे अनशन खत्म करने के लिए मत कहिए। सरकार से पूछिए कि वे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। आज (मंगलवार, 14 जुलाई) वांगचुक की भूख हड़ताल का 17वां दिन है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ CJP के विरोध-प्रदर्शन का 25वां दिन है। दिपके ने कहा कि मैं सरकार से गुज़ारिश करता हूँ कि इसे अहंकार की लड़ाई न बनाए, क्योंकि यहाँ इंसानी जानें दांव पर लगी हैं। अपनी गलती मानना कमज़ोरी की निशानी नहीं है। यह परिपक्वता, जवाबदेही और अपनी गलती सुधारने की इच्छाशक्ति की निशानी है। वांगचुक और CJP संगठन को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का समर्थन मिला है। TMC नेता महुआ मोइत्रा ने भी क्लाइमेट लीडर से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने और विरोध जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोनम सर, आपके उपवास ने इस देश के युवाओं को न्याय की लड़ाई के लिए एकजुट कर दिया है। आपका मकसद पूरा हो गया है। सरकार को आपकी या करोड़ों युवाओं की ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है।

एनआईए का खुलासा, माओवाद को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश, मगध जोन में पुराने कैडरों को किया जा रहा इकट्ठा

नई दिल्ली। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने सीपीआई (माओवादी) की एक साजिश के मामले में छठे आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला प्रतिबंधित आतंकी संगठन की मगध जोन में मौजूदगी को फिर से सक्रिय करने और हथियार व गोला-बारूद खरीदने के लिए ठेकेदारों से जबरन वसूली करने से जुड़ा है। एनआईए की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि आरोपी चंदन कुमार, माओवाद को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। हिंसा की गतिविधियों के लिए उसने मगध जोन में पुराने कैडरों को एकत्रित किया। रांची (झारखंड) में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में दाखिल अपनी तीसरी चार्जशीट में, चंदन कुमार को मामले RC-05/2021/NIA/RNC में एक मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। इस मामले को एंटी-टेरर एजेंसी ने दिसंबर 2021 में खुद संज्ञान लेते हुए दर्ज किया था।

एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बड़ा फैसला

अब अंदरूनी चोट पर भी मिलेगा दिव्यांगता कानून का लाभ

नई दिल्ली, एजेंसी। एसिड अटैक सिर्फ चेहरे या शरीर पर दिखाई देने वाले घाव ही नहीं छोड़ता, बल्कि कई बार शरीर के अंदर भी ऐसी गंभीर चोटें पहुंचाता है, जिनका असर पीड़ित की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। अब तक जिन पीड़ितों के शरीर पर बाहरी विकृति नहीं दिखती थी, उन्हें दिव्यांगता कानून के तहत मिलने वाले कई अधिकार और सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस स्थिति को बदलने का फैसला किया है।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि एसिड अटैक से आंतरिक चोट झेलने वाले पीड़ितों को भी अब दिव्यांगता अधिकार कानून के दायरे में

शामिल कर लिया गया है। इसके लिए कानून में संशोधन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि 2016 के कानून के दायरे में ऐसे एसिड हमले के पीड़ितों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद सामने आया, जिसमें अदालत ने मई 2026 में केंद्र सरकार से कहा था कि सिर्फ बाहरी रूप से विकृत दिखने वाले पीड़ितों को ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी दिव्यांगता कानून का लाभ मिलना चाहिए, जिन्हें एसिड अटैक की वजह से शरीर के अंदर गंभीर नुकसान हुआ हो। अदालत ने माना था कि आंतरिक चोटें भी व्यक्ति के सामान्य जीवन, काम करने की क्षमता और स्वास्थ्य पर उतना ही गहरा असर डाल सकती हैं जितना बाहरी घाव। इस बदलाव के बाद ऐसे पीड़ितों को भी दिव्यांगता कानून के तहत मिलने वाली सुविधाओं और अधिकारों का लाभ मिल सकेगा। इनमें सरकारी योजनाओं तक पहुंच, पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार में मिलने वाले कानूनी अधिकार तथा अन्य सहायता शामिल हो सकती है। अब केवल यह नहीं देखा जाएगा कि शरीर पर बाहरी निशान हैं या नहीं, बल्कि एसिड अटैक से हुई वास्तविक शारीरिक क्षति को भी महत्व दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी। मोहना की पीठ के समक्ष सरकार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कानून में बदलाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संशोधन कानून के लागू होने की तारीख से ही अस्तित्व में माना जाएगा।

राजनाथ सिंह का बयान 'ऑपरेशन विजय' सिर्फ़ सैन्य जीत नहीं, साहस और देशभक्ति का अध्याय था

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1999 के कारगिल युद्ध की 27वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक समारोह में 'ऑपरेशन विजय' को न केवल एक सैन्य जीत, बल्कि साहस, धैर्य, अनुशासन और देशभक्ति के प्रदर्शन के तौर पर भी बताया। मंगलवार को कारगिल विजय दिवस से पहले, सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर 'शौर्य विजय यात्रा' मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम उन भारतीय सैनिकों के साहस, बलिदान और अटूट जज़्बे को श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था।

सिंह ने कहा कि आज का यह मौका सिर्फ़ मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाने का नहीं है, बल्कि उस अटूट जज़्बे को नमन करने का है, जिसकी वजह से हमारे बहादुर नायकों

ने भारत के सम्मान, गर्व और गौरव के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। मैं उस संकल्प को नमन करने आया हूँ, जो हमारी अमर शहीदों की यादों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी ज़िंदा रखने के वादे के साथ आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने इस अभियान के नाम और मोटो (ध्येय वाक्य) का महत्व बताते हुए कहा कि इस यात्रा का नाम ही–'शौर्य विजय यात्रा' (वीरता और जीत की यात्रा)– अपने आप में एक प्रेरणा है। और इसका मोटो–'एक राइड, एक राष्ट्र, एक सलाम'–इस अभियान की भावना को बहुत गहरे और सार्थक ढंग से ज़ाहिर करता है। शायद इससे ज़्यादा सुंदर या प्रभावशाली संदेश कोई और नहीं हो सकता। युद्ध के दौरान सैनिकों की बहादुरी को याद करते हुए सिंह ने कहा कि लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर – जहां सांस लेना मुश्किल होता है, ऑक्सीजन का स्तर कम होता है और तापमान माइनस 40 डिग्री तक गिर जाता है – हमारे बहादुर सैनिकों ने ऐसे मुश्किल और विपरीत माहौल में भी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया।

महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक पर राहुल गांधी ने सीएम फडणवीस को घेरा, 3 सवालों के मांगे जवाब

नई दिल्ली। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र TET पेपर लीक पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र TET का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। 6 लाख अभ्यर्थी अधर में हैं। दो हफ्ते हो गए, नई तारीख का कोई अता-पता नहीं। लीक करने वाले आजाद, सिस्टम बेदाग और सजा भुगत रहा है वो जिसने ईमानदारी से मेहनत की। उन्होंने कहा कि ये देश के कार्यरत और होने वाले शिक्षक हैं जिनके हाथ में भारत का भविष्य है।

ये वही लोग हैं जिन्होंने साल दर साल तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस दी, दूर-दराज के सेंटर तक गए। अब बस इंतजार कर रहे हैं, बिना तारीख, बिना जवाब। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तीन चीजें आज ही बताइए।

1- समय-सीमा : TET की नई तारीख़ अभी घोषित कीजिए। 2- जवाबदेही : लीक के ज़िम्मेदारों पर कार्रवाई हो, अभ्यर्थी पर नहीं। 3- भविष्य की रक्षा : जिनका साल इस लीक के कारण बर्बाद हुआ, उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए।

SIT कर रही जांच

इस मामले की जांच SIT कर रही है। कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र कुमार गुप्ता और सोनूकुमार किशनलाल का पता लगाने के लिए फाइनेंशियल और डिजिटल सुरागों को ट्रैक किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, जांच में दिल्ली, आगरा, बिहार और हरियाणा में चल रहे एक नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। पेपर लीक होने की वजह से लगभग छह लाख उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया अधर में अटकी हुई है।

17 जुलाई को देहरादून में करूंगा बात

राहुल गांधी ने कहा कि गलती संस्था की, सजा अभ्यर्थी को मिल रहा है। ये इंसाफ नहीं है। 17 जुलाई को देहरादून में मैं पेपर लीक के बढ़ते संकट पर आपसे विस्तार से बात करूंगा। अब समय आ गया है शिक्षा क्रांति का। ऐसी व्यवस्था बनाने का, जहां युवाओं को सिस्टम की नाकामी नहीं, अपनी मेहनत का फल मिले।

इस्तीफा नहीं दूंगा, एसबीआई कर्मचारियों पर लगाए गंभीर आरोप : गोविंद देव गिरी

पुणे, एजेंसी। अयोध्या के राम मंदिर में दान की कथित चोरी के मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने मंगलवार को साफ किया कि वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने माना कि निगरानी में कुछ चूक जरूर हुई है, लेकिन खुद को व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं मानते। पुणे में मीडिया से बातचीत में गिरी महाराज ने कहा कि इस मामले में अब तक जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, वे सभी भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति और जांच की जिम्मेदारी बैंक की थी। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारियों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था। उन्होंने दान चोरी की रकम को लेकर कहा कि उनका व्यक्तिगत अनुमान करीब तीन करोड़ रुपये का है, लेकिन यह आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। उन्होंने

चल रही एसआईटी जांच और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पर संतोष जताया।

गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि उनके इस्तीफे की खबरें पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं। उन्होंने कहा, 'मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का अनुयायी हूं, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। जब लड़ने का समय होता है, तब मैदान नहीं छोड़ा जाता'। वहीं, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि यह उनका स्वैच्छिक फैसला था। ट्रस्ट के नियमों के अनुसार इस्तीफा देने के बाद उसे स्वीकार माना जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि चंपत राय की लापरवाही इस स्थिति की एक वजह रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि गड़बड़ी दान पेटियों में जमा नकदी में हुई है, ट्रस्ट के बैंक खातों में जमा पैसे सुरक्षित हैं। दान पेटियों की गिनती और हिसाब-किताब स्थानीय ट्रस्टी देखते हैं, जबकि एसबीआई को इस प्रक्रिया को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी।

अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, E20 पेट्रोल की समीक्षा की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उन गाड़ियों के लिए E20 पेट्रोल के इस्तेमाल पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है, जो इथेनॉल-मिश्रित ईंधन पर चलने के लिए नहीं बनी हैं। केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा कि पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से माइलेज कम हुआ है, इंजन जल्दी खराब हो रहा है और 2023 से पहले बनी कारों और दोपहिया वाहनों के मालिकों पर ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ा है। AAP नेता ने पेट्रोल पंपों से कहा कि वे ग्राहकों को शुद्ध पेट्रोल और E20-ब्लेंडेड फ्यूल में से चुनने का विकल्प दें। उन्होंने E20 पेट्रोल की कीमत कम करने की भी मांग की और तर्क दिया कि इस फ्यूल की कैलोरीफ़िक वैल्यू कम होने के कारण माइलेज कम मिलता है।

पहलगाम आतंकी हमले में NIA का बड़ा एक्शन, हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एक अहम घटनाक्रम के तहत, जम्मू की एक अदालत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, जिससे उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है। यह आदेश नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा 6 जुलाई को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के बाद आया है, जिसमें सईद को आरोपी बनाया गया है और आरोप लगाया गया है कि वह 22 अप्रैल, 2025 को हुए उस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर पर्यटक थे। वारंट की मांग करते हुए आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने अदालत से कहा आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है और एनआईए उससे इस मामले में आगे की कार्यवाही शुरू करने और किसी भी आगे की जांच में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अनिश्चित तिथि का गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध करती है। अपने आवेदन में एनआईए ने तर्क दिया कि सईद इस समय पाकिस्तान में है और भारतीय अदालत के समक्ष उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना संभव नहीं है। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि उसे पाकिस्तान से वापस लाने के सभी कानूनी रास्ते 'लगभग खत्म हो चुके हैं' और इसलिए उसके शारीरिक रूप से मौजूद न होने पर भी न्यायिक प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। एनआईए के मुताबिक, पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और सईद ने इस साजिश को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई थी।

'नौकरी से निकाला तो वापस रखवा देंगे', 3-लैंग्वेज पॉलिसी पर ऐसा क्यों बोले सीजेआई सूर्यकांत?

नई दिल्ली, एजेंसी। तीन भाषा नीति को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीमकोर्ट तक पहुंच गया है। इस विवाद पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि सरकार छात्रों को पर्याप्त विकल्प देने के बजाय उन पर भाषाएं थोपना चाहती है। वहीं सरकार की ओर से यह तर्क रखा गया कि नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।

दरअसल, यह पूरा मामला सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) के उस सर्कुलर से जुड़ा है, जिसमें छठवीं कक्षा से तीन भाषा के फार्मूले को लागू करने की बात कही गई है। इस फार्मूले के तहत छठवीं

कक्षा से छात्रों को भारत की दो स्थानीय भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। सीबीएसई के इस सर्कुलर के खिलाफ कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा था कि सीबीएसई ने यह फैसला अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लिया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर पेश हुए। उन्होंने कहा कि सीबीएसई के पास ऐसा सर्कुलर जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) के पास है। उनका आरोप था कि छात्रों को बिना विकल्प दिए भाषाएं पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई छात्र संस्कृत की जगह पंजाबी पढ़ना चाहता है तो उसके लिए न तो पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हैं और न ही किताबें।

रोजगार दिलाने वाली भाषाएं ही पढ़ाई जाएं

अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने अपनी दलील में कहा कि हर बच्चे को ऐसी भाषा सीखने का मौका मिलना चाहिए, जिससे भविष्य में उसे रोजगार मिलने में मदद मिल सके। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने सरकार के हलफनामे का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का दावा है कि नई पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं।

होर्मुज में दो जहाजों पर अटैक पर बढ़ा विवाद, एक भारतीय की मौत पर गुस्से में भारत, एमईए ने कर दी 5 बड़ी डिमांड

नई दिल्ली, एजेंसी। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में क्रूज मिसाइलों से संयुक्त अरब अमीरात के दो टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई। इस हमले में छह भारतीय और दो यूक्रेनी नागरिक घायल हैं। इस घटना को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई है। MEA ने होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर अटैक को लेकर टिप्पणी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय दो जहाजों, MT अल बाहिया और MT मोम्बासा पर हुए हमलों को लेकर भारत को गहरी चिंता है।

MEA ने स्टेटमेंट में कहा, 'दोनों जहाजों में मौजूद सभी 46 क्रू सदस्यों

में 30 भारतीय नाविक शामिल थे। MT अल बाहिया पर सवार 12 भारतीयों में से एक सदस्य की दुखद मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गया है। MT मोम्बासा पर सवार 18 भारतीयों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। हम मृतक भारतीय नागरिक के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं।'

विदेश मंत्रालय ने कह दी ये 5 बड़ी बातें

विदेश मंत्रालय ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हुए हमलों के बीच UAE में हमारा मिशन और पोस्ट स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। प्रभावित भारतीय नाविकों को हरसंभव मदद सुनिश्चित करने के लिए UAE अधिकारियों के संपर्क में हैं।

यही नहीं आज सुबह विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ईरान दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया। उनके समक्ष इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। MEA ने आगे कहा कि हम इन हमलों और नाविकों को निशाना बनाने और होर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और सुरक्षित आवाजाही में बाधा डालने वाली हिंसा की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं। हम पश्चिम-एशियाई क्षेत्र में हमलों के फिर से शुरू होने और तनाव बढ़ने पर अपनी गहरी चिंता भी दोहराते हैं। क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के हित में हिंसा को तुरंत रोकने और बातचीत-कूटनीति का रास्ता अपनाने का आह्वान करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि विशेष रूप से, क्षेत्र में कमर्शियल शिपिंग और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। ऐसा इसलिए जिससे अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, क्षेत्र के इंटरनेशनल जलमार्गों से मुक्त और निर्बाध आवाजाही और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके।

सीबीएसईका बड़ा फैसला, 10वीं में तीसरी भाषा का असेसमेंट पास करना हुआ अनिवार्य

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत नई भाषा नीति लागू करते हुए देशभर के स्कूलों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। बोर्ड ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि शैक्षणिक सत्र 2027-28 से कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए तीसरी भाषा (क्र3) का कोई बोर्ड एग्जाम नहीं लिया जाएगा। हालांकि, विद्यार्थियों को स्कूल लेवल पर होने वाले इंटरनल असेसमेंट में हर हाल में पास होना अनिवार्य होगा। अगर कोई छात्र स्कूल के इस असेसमेंट में फेल हो जाता है, तो उसे 10वीं कक्षा का पासिंग सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अब 9वीं कक्षा से ही विद्यार्थियों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं शामिल होनी चाहिए। बोर्ड द्वारा 10 जुलाई को जारी किए गए एक सर्कुलर में साफ बताया गया है कि कक्षा 10 के छात्रों को स्कूल-बेस्ड क्र3 (तीसरी भाषा) असेसमेंट पास करना ही होगा। जो छात्र इस इंटरनल असेसमेंट में फेल हो जाएंगे, उन्हें बोर्ड के फाइनल रिजल्ट की घोषणा से पहले अपने स्कूलों में दोबारा परीक्षा देकर इसे पास करना होगा। सीबीएसई ने छात्रों को थोड़ी राहत देते हुए यह भी कहा है कि 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा के स्कूल-बेस्ड असेसमेंट में फेल होने वाले छात्रों को उसी क्लास में रोका नहीं जाएगा। उन्हें 2027-28 के शैक्षणिक सत्र में 10वीं कक्षा में प्रमोट तो कर दिया जाएगा।

राम मंदिर चंदा विवाद का दान पर पड़ा असर, कैश की जगह अब ऑनलाइन या रसीद के साथ डोनेशन दे रहे भक्त

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में लोगों का विश्वास काफी हद तक डगमगा सा गया है। इसका असर हर दिन मंदिर में किए जाने वाले दान के तरीकों से साफ दिखाई दे रहा है। यहां आने

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में सामने आए कथित चढ़ावा चोरी मामले का असर अब श्रद्धालुओं के दान देने के तरीके पर भी साफ दिखाई देने लगा है। मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या पहले की तरह बनी हुई है, लेकिन दानपात्रों में नकद चढ़ावा लगातार घट रहा है। श्रद्धालु अब दानपात्र में नकदी डालने के बजाय ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था के तहत रसीद कटवाकर या ऑनलाइन माध्यम से दान करना

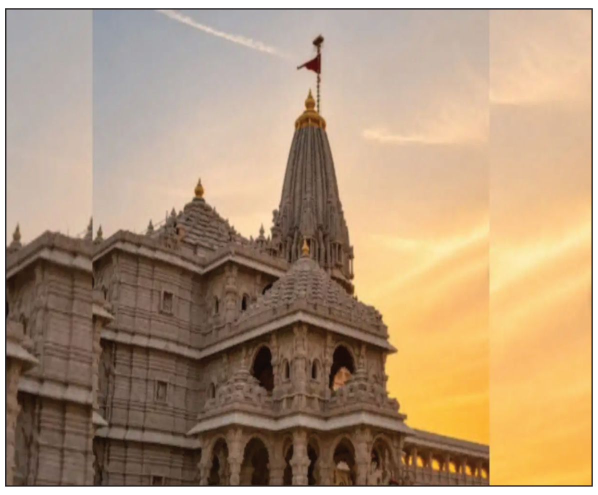

पसंद कर रहे हैं।

बैंक सूत्रों के अनुसार जून महीने में मंदिर की दानराशि के रूप में प्रतिदिन औसतन 20 से 24 लाख रुपये बैंक में जमा हो रहे थे। वहीं जुलाई में ये आंकड़ा लगातार गिरता गया और 10 जुलाई तक दैनिक जमा राशि 10 लाख रुपये से भी नीचे पहुंच गई। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 5 जुलाई को करीब 14 लाख रुपये जमा हुए थे, जबकि 10 जुलाई को यह घटकर लगभग 9।15 लाख रुपये रह गए।

डिजिटल और रसीद के जरिए बढ़ा दान

सूत्रों का कहना है कि कथित चढ़ावा चोरी विवाद के बाद श्रद्धालुओं का भरोसा दानपात्रों की बजाय रसीद आधारित और डिजिटल दान प्रणाली की ओर बढ़ा है। मंदिर में दर्शन के लिए आने वालों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई है, लेकिन दान देने के तरीके में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है।

मंदिर के एक दान काउंटर संचालक ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों से ज्यादातर श्रद्धालु दान काउंटर पर जाकर रसीद के साथ दान जमा करा रहे हैं या ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं। दानपात्रों में पहले की तुलना में काफी कम नकद राशि डाली जा रही है, जो श्रद्धालु दानपात्र में चढ़ावा अर्पित भी कर रहे हैं, वे अधिकतर 10, 20 और 50 रुपये के छोटे नोट ही डाल रहे हैं।

जुलाई में दानराशि का आंकड़ा

5 जुलाईः 14 लाख रुपये 6 जुलाईः 13।20 लाख रुपये 7 जुलाईः 12 लाख रुपये 8 जुलाईः 11 लाख रुपये 9 जुलाईः 10।25 लाख रुपये 10 जुलाईः 9।15 लाख रुपये

सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार की बनाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। ये टीम अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित हेराफेरी की जांच कर रही है। कोर्ट ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा, "हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई SIT को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हैं। इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए अगले सोमवार को लिस्ट करें। इसके साथ ही स्टेटस रिपोर्ट में SIT के सदस्यों की जानकारी भी दें।"

धनपतगंज गौशाला में 101 पौधों का पौधरोपण, पांच पर्यावरण प्रेमी सम्मानित

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। कटका क्लब सामाजिक संस्था एवं गोमती गौ रक्षा सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में धनपतगंज स्थित गौशाला पण्डरे में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 101 पौधों का पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संस्था के अध्यक्ष डॉ. सौरभ मिश्र विनम्र ने किया। उन्होंने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण को संतुलित नहीं रखते, बल्कि मानव जीवन और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अमूल्य धरोहर हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप वन प्रभागीय वनाधिकारी अंजनी श्रीवास्तव एवं जिला परियोजना अधिकारी अभिनन्दन प्रताप सिंह ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जनभागीदारी के साथ व्यापक स्तर पर पौधरोपण आवश्यक है। इस अवसर पर गोमती गौ रक्षा सेवा समिति द्वारा जनपद के पांच पर्यावरण प्रेमियों को पर्यावरण प्रेमी सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. ऋषभदेव शुक्ला एवं प्रदेश मंत्री शिव कुमार तिवारी ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण के अभियान से जुड़कर हर वर्ष पौधे लगाने और उन्हें संरक्षित करने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में गोमती गौ रक्षा सेवा समिति के अध्यक्ष सैयद अरशद अली एवं सचिव शादाब बेग ने मुख्य अतिथियों, सम्मानित अतिथियों तथा उपस्थित सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरण प्रेमी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा का जोरदार स्वागत

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा का मंगलवार को सुल्तानपुर आगमन पर महिला मोर्चा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा लखनऊ से वाराणसी जाते समय सुल्तानपुर में कुछ समय के लिए रुकीं। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रेखा निषाद, जिला उपाध्यक्ष रेनू तिवारी, भाजपा नेत्री अनिता पाण्डेय, प्रीति प्रकाश सहित अन्य पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पमाला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। स्वागत के दौरान महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा महिला कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इसके बाद वह अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत वाराणसी के लिए रवाना हो गईं।

जल जीवन मिशन के पानी से हो रही खेत की सिंचाई

कुड़वार सुल्तानपुर। हर घर को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन द्वारा बिछाई गई पाइप लाइन से खेत की सिंचाई करने का मामला प्रकाश में आया है।विभाग जांच कर कार्यवाही की बात कर रहा है।

बता दे कि कुड़वार विकास खंड के प्रतापपुर प्रथम गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत जलनिगम विभाग की पानी की टंकी का निर्माण हुआ है। पानी सप्लाई के लिए बिछाई गई पाइप के सहारे पटखापुर गांव निवासी राम शिरोमणि पाठक द्वारा खेत की सिंचाई की जा रही है। कई बार ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत विभागीय कर्मचारियों से की गई लेकिन विभाग द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। इस संबंध में विभागीय जेई रौशन कश्यप से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है आज बाहर है कल देखकर कार्यवाही करवाएंगे।

वक्फ बोर्ड में राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला, जांच की मांग ; मौलाना रजवी ने सीएम योगी को लिखा पत्र

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बरेली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में बड़े घोटालों का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इन घोटालों की जांच कराने की मांग की है। मौलाना ने दावा किया कि यदि सही दिशा में जांच हुई तो यह राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला होगा।

बरेली में मौलाना रजवी ने सोमवार शाम चार बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान वक्फ की जमीनों की खरीद-फरोख्त का अवैध कारोबार खूब फला-फूला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासनकाल में वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार लोगों ने जमीनों का सौदा किया।

मौलाना रज़वी ने बताया कि मुलायम सिंह यादव तीन बार और अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री रहे। इन सभी शासनकालों में आजम खां के पास अल्पसंख्यक, वक्फ और हज मंत्रालय रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खां के पसंदीदा लोगों को ही वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और सदस्य बनाया जाता रहा। मौलाना ने कई लोगों के नामों का जिक्र भी किया।

बोले- वक्फ की जमीनों का दुरुपयोग

मौलाना ने कहा कि वक्फ की जमीनें गरीब, कमजोर और यतीम लोगों के लिए थीं। इन जमीनों पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और मदरसे बनने चाहिए थे। लेकिन वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार लोगों ने इन जमीनों को बेचकर लूट-खसोट की। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ से होने वाली आय का सही उपयोग हो तो पूरे भारत के मुसलमानों की गरीबी दूर हो सकती है। मौलाना ने मुख्यमंत्री से दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की अपील की। प्रेस वार्ता के दौरान हाजी नसीर अहमद नूरी, मुफ्ती फारुख मिस्बाही, हाजी नाजिम बेग, राहत हुसैन मुन्ना, काशिफ खान, डॉ अनवर रज़ा कादरी और हाफिज रजी अहमद भी मौजूद रहे।

स्वच्छता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : जिलाधिकारी

जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. ने जिला स्वच्छता समिति की बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी से सफल होने वाला जनआंदोलन है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण एवं उपयोग, सामुदायिक शौचालयों की कार्यशीलता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा रिसोर्स रिकवरी सेंटर की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी ग्राम पंचायतों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण नियमित रूप से कराया जाए तथा प्रत्येक रिसोर्स रिकवरी सेंटर का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हो सके।

कासगंज में डबल मर्डर

महिला की अपहरण के बाद हत्या, गंगा में फेंका शव, पेड़ से लटकी मिली साधु की लाश

आर्यावर्त संवाददाता

कासगंज। थाना सिकंदरपुर वैश्य के कादरगंज पुख्ता निवासी में महिला मीना पत्नी नत्थू सिंह की अपहरण कर हत्या कर दी। स्वजन ने आरोपितों पर शव गंगा में फेंकने का आरोप लगाया है। वहीं कादरगंज पुल के पास गंगा किनारे रहने वाले साधु भाय सिंह का शव सोमवार सुबह 6 बजे पेड़ पर फंदे पर लटका मिला है। हत्या से पहले साधु की झोंपड़ी में आग लगा दी गई।

महिला के स्वजन का आरोप है कि साधु ने महिला का शव गंगा में फेंकते हुए आरोपितों को देख लिया था, इसलिए उनकी हत्या कर दी। उधर महिला के स्वजन ने शव बरामद करने की मांग को लेकर कादरगंज तिराहे पर जाम लगा दिया है।

महिला के बारे में बताया गया है कि वह छह जुलाई को सुबह साढ़े सात बजे गांव के सद्दाम पुत्र अजीम से अपने उधार के रुपये वापस लेने गई थी। उसके बाद वापस नहीं लौटी। मामले की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अब हत्या की तहरीर सद्दाम, शोएब और आफताब के विरुद्ध दी गई है।

पुलिस जोड़ने में लगी कड़ी

पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं। पुलिस का कहना है कि कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच की जा रही है।

किसानों की समस्या पर अपना दल का प्रदर्शन

जौनपुर। जनपद मुख्यालय पर अपना दल कमेरावादी पार्टी ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों के समस्या को लेकर धरना-प्रदर्शन करते हुए। राज्य पाल को नामित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट इन्द्र नन्दन सिंह को सौंपते हुए। मांग किया कि किसानों की इस समय चल रहा धान की रोपाई के सबसे विकट समस्या पानी व खाद को लेकर सरकार पुरी तरह से विफल है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पेट्रोल में एथेनॉल मिलावट व बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान तमाम वक्ताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस समय पूरी तरह से विफल चल रही है। प्रदेश में किसान,बेरोजगार, युवा पूरी तरह परेशान है पूरे प्रदेश में चोरी, लूट, हत्या, डकैती खुलेआम हो रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं रह गयी है। प्रदेश सरकार को ऐसी दशा में इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश सिंह, दीनानाथ सरोज, राम सिंगार पटेल, रामचंद्र पटेल, अवधेश सरोज, तेजलाल पटेल आदि उपस्थित रहे।

तीन बच्चों के साथ महिला ने खाया जहर, दो मासूम समेत तीन की मौत, एक गंभीर

आर्यावर्त संवाददाता

मिर्जापुर। जिले के मड़िहान थाना क्षेत्र के परसौना गांव में सोमवार की देर रात पारिवारिक विवाद से आहत होकर एक महिला ने अपने तीनों बच्चों को जहर खिलाकर खुद भी जहर खा लिया। हादसे में महिला, एक पुत्र और एक बेटी की मौत हो गई, जबकि एक पुत्री की हालत गंभरी बनी हुई है, जिसका वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार परसौना गांव निवासी कुसुम (38 वर्ष) ने अपने बच्चों मधु (12 वर्ष), राधिका (10 वर्ष) और सत्या (8 वर्ष) को जहर देकर खुद भी खा लिया। हालत बिगड़ने पर चारों को पीएचसी मड़िहान लाया गया, जहां से हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर किया गया।

इलाज के दौरान जिला अस्पताल में ही कुसुम और राधिका की मौत हो गई। जबकि मधु और सत्या की हालत गंभीर देख ट्रॉमा

सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान सत्या ने भी दम तोड़ दिया। वहीं मधु की हालत गंभीर बनी हुई है।

पति की दूसरी शादी के शक में उठाया खौफनाक कदम

संतनगर थाना क्षेत्र के कुसुम्हा गांव निवासी कुसुम के भाई छोटू ने बताया कि बहनोई धर्मेंद्र दिल्ली में रहता है। चार दिन पहले घर आया था। कुसुम को शक था कि उसने दूसरी शादी कर ली है। इस विवाद को लेकर 12 जुलाई रविवार को मायके शीतलगढ़ में पूर्व ग्राम प्रधान के घर समझौता हुआ था कि धर्मेंद्र 13 जुलाई सोमवार को कुसुम को विदा कराकर ले जाएगा, लेकिन वह घर आकर चला गया और विदा नहीं कराया। इसी से आहत होकर कुसुम ने यह कदम उठाया।

ईओ ने बहाली के लिए मांगे आठ लाख, बीसलपुर में बर्खास्त कर्मचारी ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखी पूरी कहानी

आर्यावर्त संवाददाता

बीसलपुर। पीलीभीत के बीसलपुर नगर पालिका की बर्खास्त कर्मचारी उपेंद्र शंखधर ने यूं ही आत्महत्या नहीं की है, वह पहले जेल जाने और फिर इंतजाम कर 18 लाख जमा करने से बुरी तरह टूट गए थे। इसके बाद सोमवार को हद तब हुई, जब दोपहर 12 बजे उन्हें फोन करके बहाली के लिए आठ लाख रुपये मांगे गए। यह कहना है उनके भाई अनुराग का। उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल करते हुए मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले की बेबसी भी उपेंद्र के पांच पेज के सुसाइड नोट से भी झलकती है।

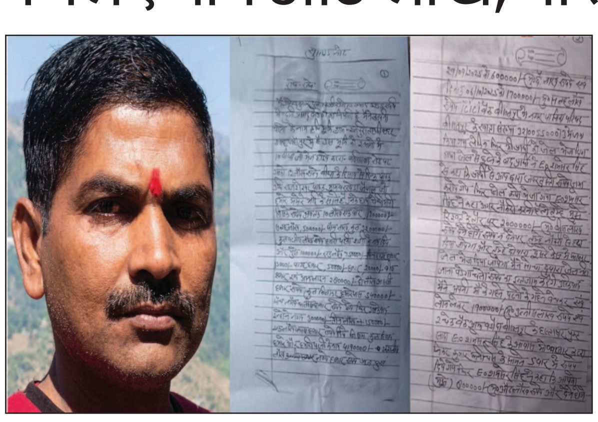

भाई अनुराग ने बताया कि खुद ईओ शमशेर सिंह ने उपेंद्र के फोन पर कॉल की। इसके बाद उपेंद्र ने घरवालों को बताया कि ईओ ने बहाली के लिए आठ लाख रुपये मांगे हैं। इसके साथ ही उपेंद्र ने कहा कि अब वह बुरी तरह टूट चुके हैं, इतनी बड़ी रकम जुटाने की हिम्मत नहीं है। घरवालों ने फिलहाल शांत रहने की सलाह देते हुए शिकायत करने को कहा। वहीं उपेंद्र ने इसके बाद अपनी जान देने की तैयारी कर ली। सितंबर में दर्ज हुआ था टैक्स घोटाले का केस

इस मामले में सितंबर 2025 में उपेंद्र शंखधर के साथ ही अनुभाग के कर्मचारी रामनिवास, जितेंद्र कुमार और पूर्व कर अधीक्षक उमेश चंद्र आनंद और अंकित वर्मा को दोषी बताते हुए रिपोर्ट लिखाई गई थी। उपेंद्र शंखधार और जितेंद्र कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उमेश, रामनिवास और अंकित इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर स्थगनादेश ले आए थे। बाद में ईओ ने रामनिवास, जितेंद्र कुमार और उपेंद्र शंखधर को दो फरवरी 2026 को बर्खास्त कर दिया था।

यह लिखा सुसाइड नोट में

पांच पन्नों के सुसाइड नोट में उपेंद्र ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शमशेर सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि बहाली और गबन प्रकरण से राहत दिलाने के नाम पर उनसे लाखों रुपये लिए गए, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। सुसाइड नोट के अनुसार, वर्ष 2025 में बर्खास्तगी के बाद उपेंद्र अपनी नौकरी बचाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। पत्नी के नाम शाहजहांपुर के तिलहर स्थित जमीन को दो भागों में बेचकर 41,90,000 रुपये मिले थे।

इसके बाद उन्होंने 29 सितंबर 2025 को छह लाख रुपये और 17 लाख रुपये छह अक्तूबर 2025 को नगर पालिका परिषद के खाता संख्या में जमा किए। इसके बावजूद उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद वह ईओ शमशेर सिंह से मिले और जबरन रुपये जमा कराने के बाद भी जेल भेजने की बात कही। पत्र में आगे लिखा गया कि इस पर ईओ ने नौकरी करने के नाम पर 20 लाख रुपये की मांग रखी। न देने पर नौकरी से हटाने और दूसरे केस में फिर जेल भेजने की चेतावनी दी। दोबारा जेल जाने के डर से उन्होंने रुपये का इंतजाम करने के लिए मां और पत्नी के गहने गिरवी रखे। साथ ही लोन लेकर कुल 19 लाख रुपये दो चेक के माध्यम ईओ को दिए।

'आठ लाख और दो, एडीएम और पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि को देना है'

सुसाइड नोट में लिखा गया कि इसके बाद ईओ ने एडीएम (पूर्व) और नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि अमन जायसवाल उर्फ निक्की को देने के लिए आठ लाख रुपये और देने को कहा। इसके बाद ही नौकरी लगने और कोर्ट में उनके पक्ष में बयान देने की ईओ ने बात कही। इस दौरान कोर्ट में कई तारीख पड़ने के बाद न तो ईओ पहुंचे न ही उनका कोई अधिवक्ता आया। इस पर उन्होंने ईओ से अपने रुपये वापस मांगे तो गालीगलौज करते हुए चेयरमैन प्रतिनिधि को अपना बताकर कुछ नहीं कर पाने की धमकी दी। कहा कि चेयरमैन प्रतिनिधि को भी हिस्सा देना होता है।

2004 से 2025 तक हर साल हुए ऑडिट, नहीं मिला गबन

सुसाइट नोट के चौथे पन्ने में लिखा गया कि वर्ष 2004 से 2025 तक हर साल ऑडिट होता है, लेकिन वह कभी गबन की कोई शिकायत में नहीं फंसे। ईओ पर आरोप लगाकर नौकरी से निकालने का जिक्र किया गया। रुपये देने के बाद एक नोटिस भेजकर गबन की शेष रकम जमा न करने पर आरसी जारी होने की बात कही। जिंदगी से परेशान होकर आत्महत्या करने पर मजबूर होने की बात कही। जिसके जिम्मेदार ईओ शमशेर सिंह और बाबू अकरम होंगे।

'विधायक जी हमारी आत्महत्या के प्रकरण को प्रमुखता से उठाना'

सुसाइड नोट के अंत में लिखा गया कि विधायक और मुख्यमंत्री से शिकायत करने के साथ ईओ शमशेर सिंह तुम्हारा क्या होगा, यह भगवान जाने। विधायक जी से अनुरोध है कि मेरी आत्महत्या के प्रकरण को प्रमुखता से उठाएं, क्योंकि ईओ कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।

ईओ के खिलाफ भी केस दर्ज करने की मांग

सुसाइड नोट में अधिशासी अधिकारी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बीसलपुर के मुहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी उपेंद्र शंखधर ने सोमवार को शाम 5:30 बजे कमरे में रस्सी से छत के कुंड में फंदा लगा लिया। परिजनों ने बताया उपेंद्र को मृतक आश्रित के तहत नौकरी मिली थी।

एसपी सुकीर्ति माधव ने कहा कि जो सुसाइड नोट मिला है। उसकी जांच हो रही है। मृतक के परिजनों की तरफ से जो भी शिकायत की जाएगी। उस आधार व जांच में जो तथ्य सामने आएंगे। उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि बीसलपुर नगर पालिका के बर्खास्त पालिका कर्मी के सुसाइड मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया जा रहा है। जांच में जो भी बातें सामने आएंगी। उस आधार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस के स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

ईओ ने स्वयं को बताया निर्दोष

सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों पर ईओ ने बात करने पर स्वयं को पूरी तरह से निर्दोष बताया है। ईओ ने कहा जो भी आरोप उन पर लगे हैं। वह निराधार हैं। पूरे मामले की जांच के बाद सारी हकीकत सामने आ जाएगी।

नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि अमन जायवाल उर्फ निक्की ने कहा कि मेरा इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है, न ही मैने कभी कोई हस्तक्षेप किया है। नगर पालिका में हुए टैक्स घोटाले में जो भी कार्रवाई हुई व प्रशासन के स्तर से की गई है।

वन नेशन, वन इलेक्शन' पर लखनऊ में मंथन, ए.के. शर्मा बोले—एक साथ चुनाव से विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (एक राष्ट्र-एक चुनाव) के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सदस्यों के साथ मंगलवार को राजधानी लखनऊ के एक होटल में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने हिस्सा लिया और इस व्यवस्था के पक्ष में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस दौरान एक साथ चुनाव कराने के साथ-साथ 'वन वोटर लिस्ट' की व्यवस्था का भी समर्थन किया गया।बैठक में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष अपने सुझाव रखते हुए कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और राष्ट्रहित में किया गया एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसे शीघ्र लागू किया जाना चाहिए।ए.के. शर्मा ने कहा कि वर्ष 2021 से राजनीति में सक्रिय रहने के दौरान उन्होंने लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर निकाय सहित कई चुनाव देखे हैं। उनके अनुसार, वर्ष 2021 से 2029 तक आठ वर्षों में आठ अलग-अलग चुनाव होने की स्थिति बनती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चुनाव से पहले दो से तीन महीने तक पूरा प्रशासन चुनावी तैयारियों में व्यस्त रहता है और चुनाव के बाद भी कुछ समय तक सामान्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित रहते हैं। इसका सीधा असर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और सरकारी

कामकाज पर पड़ता है।उन्होंने कहा कि यदि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो चुनावों की आवृत्ति कम होगी, सरकारी खर्च में उल्लेखनीय कमी आएगी और सुरक्षा बलों की बार-बार तैनाती की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इससे प्रशासन को विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर अधिक समय और संसाधन लगाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और आम जनता को समयबद्ध एवं प्रभावी सेवाएं मिल सकेंगी।ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ने बैठक में 'वन वोटर लिस्ट' का भी समर्थन करते हुए कहा कि यदि पूरे देश में एक समान मतदाता सूची की व्यवस्था लागू होती है तो चुनावी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, सरल तथा प्रभावी बनेगी।ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत' का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक दक्षता, नीति निर्माण में निरंतरता और विकास कार्यों की गति बनाए रखना आवश्यक है। उनके अनुसार, 'वन नेशन, वन इलेक्शन' इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक मजबूत और विकासोन्मुख बनाएगा।बैठक में उपस्थित उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इसे देशहित में आवश्यक सुधार बताया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह व्यवस्था देश के व्यापक हित में है और इस पर सभी राजनीतिक दलों तथा समाज के विभिन्न वर्गों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि एक साथ चुनाव होने से लोकतंत्र और अधिक सशक्त होगा, विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकेगी।बैठक में संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों के साथ 'वन नेशन, वन इलेक्शन' से जुड़े संवैधानिक, प्रशासनिक और व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा विभिन्न सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया। सरकार की ओर से उम्मीद जताई गई कि इस व्यवस्था के लागू होने से देश में सुशासन, विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नई दिशा मिलेगी।

एक राष्ट्र, एक चुनाव' के समर्थन में उत्तर प्रदेश विधान परिषद का प्रस्ताव

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत 129वां संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 तथा संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 का स्वागत करते हुए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (वन नेशन, वन इलेक्शन) व्यवस्था को देशहित में आवश्यक सुधार बताया है। परिषद ने केंद्र सरकार से इस व्यवस्था को शीघ्र लागू करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे सरकारी संसाधनों की बचत, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि और विकास कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित होगी।विधान परिषद की ओर से जारी प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान व्यवस्था में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव अलग-अलग समय पर होने के कारण केंद्र और राज्य सरकारों पर आर्थिक तथा प्रशासनिक बोझ बढ़ जाता है। प्रत्येक चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था, चुनावी सामग्री, मतदान कर्मियों और प्रशासनिक संसाधनों की अलग-अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। कई बार एक ही वर्ष में अनेक चुनाव होने से सरकारी मशीनरी लंबे समय तक चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहती है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं।परिषद का मत है कि यदि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं तो हजारों करोड़ रुपये की बचत संभव होगी। इस धन का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे के विकास, कृषि के आधुनिकीकरण और गरीबी उन्मूलन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं में किया जा सकेगा। प्रस्ताव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का भी उल्लेख किया गया है। परिषद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे विद्यालयों में पढ़ाई, परीक्षाएं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक और कर्मचारी भी चुनावी दायित्वों में लगाए जाते हैं, जिससे अस्पतालों का संचालन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण अभियान तथा जनस्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव होने से इन आवश्यक सेवाओं में बाधा नहीं आएगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो सकेंगी।विधान परिषद ने कहा कि बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू होने से विकास परियोजनाओं की गति धीमी पड़ जाती है। यदि चुनाव एक निर्धारित चक्र में एक साथ कराए जाएं तो जिला प्रशासन, नगर निकाय, ग्राम पंचायतें और विकास प्राधिकरण योजनाओं का बेहतर समन्वय के साथ क्रियान्वयन कर सकेंगे। साथ ही प्रशासन को डिजिटल गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाओं और पारदर्शी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिक समय मिलेगा।प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश एक द्विसदनीय विधानमंडल वाला राज्य है और विधान परिषद एक स्थायी सदन के रूप में विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बार-बार चुनाव होने से सरकार और प्रशासन का पर्याप्त समय चुनावी तैयारियों में व्यतीत होता है। यदि चुनाव एक साथ होंगे तो विधान परिषद को विधेयकों, नीतियों और विकास योजनाओं पर अधिक गंभीरता से चर्चा करने तथा समितियों के माध्यम से विभागीय कार्यों की प्रभावी समीक्षा करने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले अनुराग ठाकुर, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।

मुलाकात के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को उत्तर प्रदेश सरकार 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' की अवधारणा के माध्यम से आगे बढ़ा रही है।अनुराग ठाकुर ने कहा कि योगी सरकार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय और सराहनीय प्रयास कर रही है। उनके अनुसार, राज्य में विकास और जनकल्याण को केंद्र में रखकर

अनेक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश भयमुक्त और माफियामुक्त वातावरण की ओर बढ़ा है तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और लोककल्याण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं।मुख्यमंत्री और अनुराग ठाकुर की मुलाकात के दौरान प्रदेश के विकास, सुशासन तथा अन्य समसामयिक विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

यूपी पावर कॉरपोरेशन में दो सहायक अभियंताओं का तबादला, अनुरोध पर जारी हुए स्थानांतरण आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने दो सहायक अभियंताओं के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। दोनों अधिकारियों का तबादला उनके स्वयं के अनुरोध पर किया गया है। इस संबंध में उप सचिव (04) कुमार अभिजीत रंजन द्वारा अलग-अलग कार्यालय ज्ञापन जारी किए गए हैं।जारी आदेश के अनुसार, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा में तैनात सहायक अभियंता सुरेंद्र सिंह (आईडी-11004873/2017021), जिनका गृह जनपद अलीगढ़ है, का स्थानांतरण उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में किया गया है। वहीं, दूसरे आदेश में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा में कार्यरत सहायक अभियंता रवि पाण्डेय (आईडी-11006812/2021167), जिनका गृह जनपद गोंडा है।

पीजीटी परिणाम को लेकर अफवाहों से सावधान रहें, भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीईएसएससी) ने पीजीटी, टीईटी और अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही भ्रामक सूचनाओं पर अभ्यर्थियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कुछ लोग अभ्यर्थियों को गुमराह कर आयोग में प्रार्थना पत्र देने के लिए उकसा रहे हैं तथा ओएमआर शीट, उत्तर कुंजी, कटऑफ, प्राप्तांक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के माध्यम से तैयार किए गए कथित दस्तावेजों के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं।आयोग की ओर से मंगलवार को जारी महत्वपूर्ण सूचना में कहा गया है कि उसके संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्ति सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अभ्यर्थियों को भ्रामक एवं अप्रमाणित जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही धन के लेन-देन से जुड़े भ्रामक दावे भी किए जा रहे हैं, जिनका आयोग से कोई संबंध नहीं है।आयोग ने स्पष्ट किया कि पीजीटी परीक्षा का परिणाम पहले ही घोषित किया जा चुका है। सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक तथा चयनित अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा अंक, साक्षात्कार अंक और अंतिम प्राप्तांक आयोग की ओर से अलग-अलग प्रदर्शित किए जा चुके हैं। इसलिए अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें।शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा कि अभ्यर्थी केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और भर्ती विज्ञापन के समय जारी की गई अधिकृत सूचनाओं को ही प्रामाणिक मानें। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति, सोशल मीडिया पोस्ट या अन्य माध्यमों से प्रसारित जानकारी के आधार पर कोई कदम न उठाएं।

मेकअप के बहाने घर से निकली किशोरी सकुशल बरामद, अपहरण के आरोपी को मड़ियांव पुलिस ने किया गिरफ्तार

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की मड़ियांव थाना पुलिस ने 17 वर्षीय किशोरी के कथित अपहरण के मामले का खुलासा करते हुए उसे सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में नामजद आरोपी को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच के साथ ही आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटा रही है।पुलिस के अनुसार, 10 जुलाई 2026 को पीड़िता की मां ने मड़ियांव थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री को एक युवती मेकअप कराने के बहाने घर से बाहर बुलाकर ले गई, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आशंका जताई कि रवि नामक युवक उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।शिकायत के आधार पर मड़ियांव थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) और 87 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

यूपी की होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति में बड़ा बदलाव, अब 8 कमरे तक होंगे पंजीकरण के पात्र

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति-2025 को अधिक व्यावहारिक और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से इसके कई प्रावधानों में संशोधन किया है। संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत अब होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों में पहले की तुलना में अधिक कमरों का पंजीकरण कराया जा सकेगा। साथ ही पंजीकरण प्रमाणपत्र के ऑटो रिन्यूअल की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि संशोधित एसओपी के अनुसार अब होम स्टे प्रतिष्ठानों में न्यूनतम एक और अधिकतम आठ कमरे पंजीकृत कराए जा सकेंगे। हालांकि, जिन भवनों में नौ या उससे अधिक कमरे होंगे, वे इस नीति के तहत पंजीकरण के पात्र नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि होम स्टे की मूल अवधारणा को बनाए रखने के लिए प्रतिष्ठान का मालिक या उसका परिवार उसी भवन में निवासरत होना अनिवार्य रहेगा।मंत्री ने बताया कि बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों के लिए भी यही व्यवस्था लागू की गई है। इनमें भी एक से आठ कमरों तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। इसके अलावा 16 बिस्तरों वाली डॉरमेट्री को भी इस श्रेणी में पात्र इकाई के रूप में शामिल किया गया है। पहले यह सीमा 12 बिस्तरों तक ही थी।

उन्होंने कहा कि होम स्टे, ग्रामीण होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों के पंजीकरण प्रमाणपत्र का ऑटो रिन्यूअल अब उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के पोर्टल पर आवेदक स्वयं कर सकेंगे। यह प्रक्रिया प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने से तीन माह पहले शुरू की जा सकेगी।जयवीर सिंह ने बताया कि यदि कोई आवेदक निर्धारित समय के भीतर ऑटो रिन्यूअल नहीं कराता है, तो उसके आवेदन पर निर्णय जिला स्तरीय समिति करेगी। इसके लिए आवेदक को विलंब का पर्याप्त और उचित कारण प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि इससे पहले जारी एसओपी के तहत होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों में अधिकतम छह कमरे ही किराये पर देने की अनुमति थी तथा डॉरमेट्री की क्षमता भी 12 बिस्तरों तक सीमित थी। संशोधन के बाद कमरों और बिस्तरों की संख्या बढ़ने से अधिक लोगों को इस नीति का लाभ मिल सकेगा और प्रदेश में पर्यटन आधारित रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।राज्य सरकार का मानना है कि इन संशोधनों से होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों का संचालन आसान होगा, पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार और ग्रामीण पर्यटन को नई गति मिलेगी।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की मासिक समीक्षा बैठक मंगलवार को आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में महिला सुरक्षा, महिला कल्याण और विभिन्न संस्थानों के निरीक्षण की प्रगति की समीक्षा के साथ आगामी माह की कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक का शुभारंभ आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान, उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और उपाध्यक्ष चारू चौधरी द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इसके बाद आयोग के पदाधिकारियों ने बीते माह के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किए गए निरीक्षणों और जनसुनवाई कार्यक्रमों की समीक्षा की।बैठक में आयोग की अध्यक्ष ने महिला जनसुनवाई, वन स्टॉप सेंटर, महिला चिकित्सालयों, महिला बंदीगृहों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान सामने आए बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की।

गुमशुदा युवक की मौत के मामले में दंपती गिरफ्तार, एक बाल अपचारी भी संरक्षण में लिया गया

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी के सआदतगंज थाना क्षेत्र से लापता हुए 18 वर्षीय युवक की मौत के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में कथित रूप से शामिल एक बाल अपचारी को विधिक प्रावधानों के तहत संरक्षण में लिया गया है। पुलिस का आरोप है कि सड़क दुर्घटना में युवक के घायल होने के बाद आरोपी उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गए थे।

पुलिस के अनुसार, 17 जून 2026 को सआदतगंज निवासी आसिफ ने अपने 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सैफ की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों एवं अन्य तथ्यों के आधार पर जांच शुरू की।जांच में पता चला कि 15 जून को

मोहम्मद सैफ अपने एक बाल अपचारी मित्र के साथ मोटरसाइकिल से बाराबंकी जा रहा था। इसी दौरान कोतवाली नगर क्षेत्र में हिन्द मेडिकल के पास सड़क दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, आरोप है कि दुर्घटना के बाद साथ मौजूद लोग घायल युवक को मौके पर छोड़कर चले गए और न तो उसके परिजनों को सूचना दी और न ही पुलिस को।सआदतगंज पुलिस ने बाराबंकी पुलिस से समन्वय कर जानकारी जुटाई, जिसमें पता चला कि स्थानीय पुलिस ने दुर्घटना के दिन घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उस समय उसकी पहचान नहीं हो सकी थी, जिसके चलते बाराबंकी पुलिस ने अज्ञात शव के रूप में पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई थी।बाद में युवक की पहचान और मौत की पुष्टि होने पर मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर सआदतगंज थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुस्कान उर्फ सैय्यद आफरीन (21 वर्ष) और सुमित गुप्ता उर्फ गोलू (26 वर्ष) को रेड पैथ लैब के पास से गिरफ्तार कर लिया। वहीं, घटना में कथित रूप से शामिल एक 17 वर्षीय बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

ओआरएस व जिंक की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं : डॉ. मंजू सचान

'डायरिया से डर नहीं' कार्यक्रम की मंडलीय समीक्षा बैठक

स्टॉप डायरिया कैंपेन के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों पर हुई चर्चा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

आगरा। स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में मंगलवार को अपर निदेशक कार्यालय के सभागार में 'डायरिया से डर नहीं' कार्यक्रम की मंडलीय समीक्षा बैठक हुई। पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पी. एस. आई. इंडिया) और केनव्यू के सहयोग से आयोजित बैठक की अध्यक्षता अपर निदेशक चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. मंजू सचान ने की। बैठक में आगरा के साथ ही मंडल के

मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिले के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में शून्य से पांच साल तक के बच्चों में डायरिया रोग प्रबन्धन के लिए इस समय चल रहे स्टॉप डायरिया कैम्पेन (दस्त रोको अभियान) के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

अपर निदेशक ने कहा कि शून्य से पांच साल तक के बच्चों की मौत का एक प्रमुख कारण डायरिया भी है, जबकि दस्त की रोकथाम और उपचार पूरी तरह संभव है। इसलिए डायरिया से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चे को दिन भर में तीन या तीन से अधिक बार दस्त हो तो समझना चाहिए कि बच्चा डायरिया से ग्रसित है और ऐसे में उसको तत्काल ओआरएस का घोल देना चाहिए ताकि शरीर में पानी और नमक की कमी न होने पाए, साथ ही निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करना चाहिए। उन्होंने स्टॉप डायरिया कैम्पेन में पीएसआई इंडिया के सहयोग को सराहा I इसके साथ ही मंडल के सभी जिलों के विभागीय अधिकारियों से कहा कि संस्था का सहयोग करते हुए डायरिया रोको अभियान 2026 की समस्त गतिविधियों को ससमय सम्पन्न कराएं और ओआरएस व जिंक की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित कराएं। बैठक में संयुक्त निदेशक (जेडी) डॉ. नीरज त्यागी ने हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) की रिपोर्ट की समीक्षा की। उन्होंने एचएमआईएस आपरेटर को निर्देशित किया कि इस माह रिपोर्ट सही तरीके से तैयार की जाए। डिवीज़नल कार्यक्रम प्रबन्धक पवन कुमार ने सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधकों से कहा कि आंकड़ों का मूल्यांकन करते हुए डायरिया केस की रिपोर्टिंग सुनिश्चित कराएँ। डिवीज़नल अर्बन हेल्थ सलाहकार इरसाद और डिविजनल एमएनई अफजल ने कहा कि डायरिया की पहचान एवं रिपोर्टिंग अर्बन फैसिलिटी पर सुनिश्चित कराएं।

पी. एस. आई. इंडिया के सीनियर मैनेजर प्रोग्राम अनिल द्विवेदी ने 'डायरिया से डर नहीं' कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के तहत मण्डल के आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद जनपदों में आशा कार्यकर्ताओं, आशा संगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पीएसआई इंडिया के सहयोग से प्रशिक्षित किया गया है I इसके साथ ही डायरिया रोको अभियान (स्टॉप डायरिया कैम्पेन) के दौरान ई-रिक्शा के माध्यम से डायरिया से बचाव और प्रबन्धन के बारे में प्रचार-प्रसार किया जाएगा, जिसमें सभी का सहयोग जरूरी है। प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण किया जाना है। सरकारी और निजी अस्पतालों में अब तक बनाए ओआर एस कार्नर का डाटा भी प्रस्तुत किया। बैठक में फ़रीज़ाबाद के डीपीएम भानु प्रताप, आगरा के अर्बन नोडल अधिकारी डॉ. ऋषि गोपाल, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ.उपेंद्र कुमार, डीपीएम कुलदीप भारद्वाज, नगरीय स्वास्थ्य समन्वयक आकाश गौतम, जनपद मथुरा से जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. रोहिताश सिंह, डीपीएम संजय सिहोरिया, जिला लेखा प्रबंधक, मैनपुरी के डीपीएम, अर्बन हेल्थ समन्वयक, एचएमआईएस ऑपरेटर और पीएसआई इंडिया की ओर से राजेश कुमार प्रजापति, अजय कुमार, पंकज कुमार आदि उपस्थित रहे।

रहीमाबाद पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, पांच चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद, दो गिरफ्तार

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की रहीमाबाद थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे और निशानदेही पर विभिन्न स्थानों से चोरी की गई पांच मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।पुलिस के अनुसार, 13 जुलाई को रहीमाबाद थाना पुलिस अपराध नियंत्रण, संदिग्ध व्यक्तियों की जांच और वांछित आरोपियों की तलाश में क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर तीन चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।इसके बाद राकेश से की गई गहन पूछताछ में उसने अपने साथी सुनील और मनीष के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार की।

प्रधानमंत्री मोदी को मिले पुरस्कारों पर गार्जियन की हताशा

दा गार्जियन अखबार ने मोदी और भारत की छवि धूमिल करने के लिए एक अंग्रेजी मे एक लेख लिखा। जिसका सारांश यह है कि कोई झूठे भी पुरस्कार देने के लिए बुलाए तो प्रधानमंत्री मोदी दौड़े दौड़े चले जाते हैं। मतलब यह अखबार कहना चाह रहा कि मोदी पुरस्कार के भूखे हैं, साथ ही यह भी जताने की कोशिश कर रहा है, जिन देशों ने मोदी को उनकी विदेश यात्रा के दौरान पुरस्कार दिए, उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को इन देशों ने फिजूल में पुरस्कार दिए हैं। गार्जियन ने यह लेख लिख कर मोदी सहित भारत का तो अपमान किया ही है, साथ मोदी को पुरस्कार देने वाले उन देशों के नागरिकों, पुरस्कारों और उन देशों के राष्ट्रप्रमुखों का भी अपमान किया है। इस लेख की भड़ास के बावजूद पीएम मोदी को पुरस्कारों का सिलसिला थम नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान 'बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया' मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रदान किया। वर्ष 2016 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के देशों से ऐसे 34 सम्मान मिल चुके हैं। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को मिले सम्मानों में सबसे अधिक हैं। इनमें से कुछ सम्मान सदियों पुराने हैं, जबकि कुछ सम्मान संबंधित देशों की सम्मान प्रणाली में हाल ही में शामिल किए गए हैं। गार्जियन का यह लेख में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का कुत्सित प्रयास है। विश्व का बड़ा और प्रभावशाली शायद ही कोई देश बचा होगा जिसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने मोदी और भारत की तारीफ नहीं की होगी। दरअसल यह तारीफ पाश्चात्य मीडिया पचा नहीं पा रहा है, पचा इसलिए भी नहीं पा रहा है कि भारत न सिर्फ घरेलू स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तरक्की के झंडे गाढ़ रहा है। चंद्रयान और मंगलयान मिशन की कामयाबी इसके बड़े उदाहरण हैं। जो विकसित देश भी हासिल नहीं कर सके। यह अखबार यह भी भूल गया कि जब कोरोना काल में पूरी दुनियां में हाहाकार मचा हुआ था, तब भारत ने ही कोरोना वैक्सीन दर्जनों देशों को निशुल्क भेज कर करोड़ों लोगों की जाने बचाने का काम किया था। क्या ऐसे परोपकारी कार्यों के लिए उन्हें विदेशी पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। गार्जियन ने इसका जिक्र कभी नही किया कि विश्व को मोदी नेतृत्व में भारत ने क्या—क्या दिया है। भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसी सस्ती और सुलभ डिजिटल पेमेंट प्रणाली नेपाल, भूटान, सिंगापुर, यूएई और मॉरीशस ने अपना लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की प्राचीन धरोहर योग को मोदी सरकार के प्रयासों से वैश्विक मान्यता मिली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में मनाया जाता है। मोदी सरकार के प्रयासों से ही अफ्रीकी संघ को जी-20 का स्थायी सदस्य बनाया गया।

भारत ने प्राकृतिक आपदा के दौरान विश्व के देशों के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा रहा है। तुर्किये और सीरिया में आए भूकंप के दौरान'मिशन सागर'और'ऑपरेशन दोस्त'के जरिए विश्व स्तर पर मानवीय सहायता पहुंचाई गई। वेनेज़ुएला में विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत बचाव दल और पोर्टेबल अस्पताल भेजे गए। म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा (2025) और ऑपरेशन सहायता (2008) के तहत भूकंप व चक्रवात के दौरान भारी राहत सामग्री व चिकित्सा सुविधाएँ दी गईं। श्रीलंका में सुनामी (2004) में ऑपरेशन रेनबो और चक्रवात (2025) में ऑपरेशन सागर बंधु के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

भारतीय नौसेना ने हालिया समुद्री सुरक्षा अभियानों (मुख्य रूप से अरब सागर और अदन की खाड़ी) में 520 से अधिक लोगों की जान बचाई है और ईरान, लाइबेरिया, माल्टा, और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइन्स जैसे विभिन्न देशों के झंडे वाले जहाजों को समुद्री लुटेरों से सुरक्षित मुक्त कराया है। इन अभियानों की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि नौसेना ने बिना किसी राष्ट्रीय भेदभाव के, पाकिस्तानी और ईरानी नागरिकों सहित कई देशों के नाविकों को भी बचाया है। गार्जियन खासकर विदेशी मीडिया को कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भारी परेशानी है। भारत में उन्हें यह उल्लंघन नजर आता है। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया। अंग्रेज शासकों ने इस अवधि में भारतीयों पर अत्याचारों के सारे रिकार्ड तोड़ दिए। अंग्रेज व्यापारी बन कर आए और तानाशाह बन बैठे, खूब लूट खसौट की और भारत से सारा मालमत्ता समेट कर चंपत हो गए। आज भी कोहिनूर का हीरा इन्हीं अंग्रेजों के पास है, जो यह बताता है कि किस तरह इन्होंने भारत में लूटपाट मचाई थी। ऐसे मानवाधिकारों के उल्लंघन गार्जियन जैसे अखबारों को दिखाई नहीं देते। मानवाधिकारों के इन विदेशी पैरोकारों को जलियांवाला बाग दिखाई नहीं देता, जहां निहत्थे प्रदर्शकारियों को चारों तरफ से घेर कर एक अंग्रेज अधिकारी डायर ने गोलियों से भून डाला था।

सतलुज विवाद पर रवनीत सिंह बिट्टू ने जो सवाल उठाये हैं क्या दिलजीत दोसांझ उनका जवाब देंगे?

हम आपको बता दें कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब सतलुज ओटीटी पर रिलीज होने के महज दो दिन बाद ही वहां से हटा ली गई।

नीरज कुमार दुबे

पंजाब की राजनीति में एक बार फिर इतिहास, सिनेमा और सियासत आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह राजनीतिक बहस में बदल गया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने दिलजीत दोसांझ और फिल्म के निर्देशक हनी त्रेहन पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि फिल्म के जरिए पंजाब के उग्रवाद के दौर की केवल एकतरफा तस्वीर पेश की जा रही है और समाज में पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि केंद्र सरकार का फिल्म को ओटीटी मंच से हटाने में कोई हाथ नहीं है। साथ ही उन्होंने पूरे विवाद को सुनियोजित प्रचार करार दिया।

हम आपको बता दें कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब सतलुज ओटीटी पर रिलीज होने के महज दो दिन बाद ही वहां से हटा ली गई। इस कदम के बाद पंजाब के फिल्म जगत, सोशल मीडिया और पंजाब सरकार के कुछ हलकों में यह सवाल उठने लगे कि क्या राजनीतिक दबाव के चलते फिल्म हटाई गई। हालांकि रवनीत सिंह बिट्टू ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि सरकार का ऐसे मंचों पर कोई नियंत्रण नहीं है। उनका दावा है कि फिल्म के निर्माताओं ने स्वयं ही इसे हटाया क्योंकि उन्हें जितना आर्थिक लाभ चाहिए था, वह मिल चुका था। उन्होंने कहा कि जब स्वयं दिलजीत दोसांझ पहले ही यह कह चुके थे कि फिल्म केवल दो तीन दिन के लिए उपलब्ध रहेगी, तभी समझ जाना चाहिए था कि पूरे घटनाक्रम में कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को फिल्म हटानी ही होती तो उसे प्रसारित होने की अनुमति ही क्यों दी जाती। बिट्टू ने आरोप लगाया कि पहले फिल्म को प्रसारित कर माहौल बनाया गया और फिर उसे हटाकर सरकार पर प्रतिबंध लगाने का आरोप मढ़ दिया गया।

केंद्रीय मंत्री ने दिलजीत दोसांझ पर केवल इस विवाद तक हमला सीमित नहीं रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिलजीत केवल धन कमाने के लिए काम करते हैं और विदेश में बैठकर पंजाब के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें बहुरूपिया बताते हुए कहा कि वह लॉस एंजिलिस में रहकर पंजाब की भावनाओं से खेल रहे हैं। बिट्टू ने सवाल उठाया कि यदि दिलजीत को समाज और मानवाधिकारों की इतनी चिंता है तो उन्होंने मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा पर फिल्म क्यों नहीं बनाई? उन्होंने फिल्म चमकीला का भी जिक्र करते हुए कहा कि यदि दिलजीत अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान करते तो ऐसी फिल्म में काम नहीं करते। उन्होंने यह दावा भी किया कि विदेशों में अपने कार्यक्रमों के दौरान दिलजीत खालिस्तान के झंडे लेकर आने वालों को हटाने की बात करते हैं और फिर सवाल उठाया कि आखिर उनके पीछे कौन-सी ताकतें काम कर रही हैं? रवनीत सिंह बिट्टू ने स्पष्ट किया कि उन्हें पंजाब में उग्रवाद के दौर पर फिल्म बनने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका विरोध केवल एकतरफा कहानी दिखाने को लेकर है। उन्होंने कहा कि यदि उस दौर की कहानी दिखाई जा रही है तो उन पुलिस अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों और निर्दोष नागरिकों के बलिदान को भी सामने लाया जाना चाहिए जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपने प्राण गंवाए। उन्होंने दिलजीत दोसांझ और हनी त्रेहन को चुनौती देते हुए पूछा कि क्या वह उन पुलिस अधिकारियों और आम नागरिकों पर भी फिल्म बनाएंगे जिनकी 1984 के बाद के दौर में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। उन्होंने लालडू के पास एक सौ पच्चीस यात्रियों के नरसंहार और युवा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अविंदर सिंह की हत्या जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन परिवारों के दर्द को भी देश के सामने लाया जाना चाहिए। फिल्म में किए गए उस दावे पर भी केंद्रीय मंत्री ने सवाल उठाया जिसमें पच्चीस हजार अज्ञात शवों के गुप्त तरीके से निपटान की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि यदि यह दावा तथ्यात्मक है तो निर्माता उसके प्रमाण सार्वजनिक करें। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि पच्चीस हजार तो दूर, यदि पांच हजार मामलों का भी पूरा ब्यौरा मीडिया, संबंधित आयोग या न्यायालय के सामने रख दिया जाए तो वह अपनी बात वापस लेने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तथ्यों के बिना ऐसे गंभीर आरोप समाज में भ्रम और तनाव पैदा करते हैं। अपने परिवार के इतिहास का जिक्र करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि उनके दादा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह ने आतंकवाद के कठिन दौर में राज्य में शांति बहाल करने के लिए संघर्ष किया था और इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि उस समय पंजाब में भय का ऐसा माहौल था कि सामान्य सामाजिक जीवन भी प्रभावित हो गया था। विवाह समारोहों से लेकर महिलाओं के पहनावे तक पर आतंक का साया था। उन्होंने उस दौर की तुलना कट्टर शासन से करते हुए कहा कि आज की शांति बहुत कठिन संघर्ष के बाद मिली है और इसे केवल फिल्म की कमाई या राजनीतिक लाभ के लिए दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म में घटनाक्रम की समयरेखा को लेकर गंभीर सवाल हैं। उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह खालरा के लापता होने की घटना उनके दादा की हत्या के बाद हुई थी और उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में उस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी किसकी थी, इस पर भी सवाल उठना चाहिए। उन्होंने अकाली दल पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि गांवों और गुरुद्वारों में फिल्म का प्रदर्शन कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जसवंत सिंह खालरा की पत्नी ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर भी गंभीर आरोप लगाए थे, जिनकी चर्चा आज नहीं की जाती। साथ ही रवनीत सिंह बिट्टू ने सोशल मीडिया पर भी अपनी बात विस्तार से रखते हुए कहा कि इतिहास की केवल एक तरफा नहीं, बल्कि पूरी सच्चाई को जानना जरूरी है। उन्होंने लिखा कि पंजाब ने अपने निर्दोष लोगों के बलिदान के साथ जो असहनीय पीड़ा झेली है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उनका कहना था कि हर पीड़ित को याद किया जाना चाहिए और हर पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्थायी और वास्तविक शांति केवल सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। बिट्टू के अनुसार यदि इतिहास के केवल एक हिस्से को दिखाया जाएगा और दूसरे पक्ष के दर्द तथा बलिदान को नजरअंदाज किया जाएगा तो समाज में संतुलित विमर्श कभी स्थापित नहीं हो सकेगा। उनका कहना है कि पंजाब के उग्रवाद के दौर की कहानी में केवल कुछ घटनाओं या कुछ पात्रों को केंद्र में रखना न्यायसंगत नहीं है, बल्कि उन हजारों निर्दोष परिवारों, पुलिसकर्मियों, सुरक्षाबलों और आम नागरिकों के दर्द को भी बराबर महत्व मिलना चाहिए जिन्होंने आतंकवाद की कीमत अपने जीवन से चुकाई। बहरहाल, फिलहाल सतलुज को लेकर छिड़ा विवाद केवल एक फिल्म तक सीमित नहीं रह गया है। यह बहस अब इतिहास की व्याख्या, राजनीतिक विमर्श, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पंजाब के उग्रवाद वाले दौर की स्मृतियों तक पहुंच चुकी है। एक पक्ष इसे दबाई गई सच्चाइयों को सामने लाने का प्रयास बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे अधूरी और एकतरफा कहानी के जरिए समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश मान रहा है। ऐसे में यह विवाद आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति और जनचर्चा दोनों के केंद्र में बना रहने के संकेत दे रहा है।

व्यंग्य

पानी की किल्लत से ग्रस्त

डेटा सेंटर उन क्षेत्रों में बन रहे हैं, जो पानी की किल्लत से ग्रस्त हैं। भारत डेटा सेंटरों में जल उपयोग को लेकर फिलहाल अनिवार्य पर्यावरण मानक या अनिवार्य रिपोर्टिंग के नियम मौजूद नहीं हैं।

हर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस डेटा सेंटर की स्थापना की खबर को भारत में एक बड़ी उपलब्धि समझा जाता है। इनसे विदेशी निवेश के रूप में आने वाले डॉलर की खबर उस समय और महत्त्वपूर्ण हो गई है, जब देश के सामने भुगतान संतुलन की चुनौती बढ़ रही है। मगर डेटा सेंटर्स के साथ एक अन्य बड़ी समस्या भारत आ रही है। ये वो समस्या है, जिसके कारण डेटा सेंटर्स विभिन्न अमेरिकी राज्यों में बेहद अलोकप्रिय हो गए हैं। इन सेंटर्स के लिए पानी और बिजली की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है कि उससे भविष्य बिगड़ने की आशंका से कई अमेरिकी राज्यों में ये सेंटर्स बड़े जन प्रतिरोध का कारण बने हुए हैं।

मगर भारत में इनको लेकर जागरूकता की अभी कमी है। जबकि गैर-सरकारी संस्था-काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में भारत के डेटा सेंटरों ने सालाना 150 अरब लीटर पानी की खपत की। इन सेंटर्स की बढ़ती संख्या के कारण 2030 तक यह आंकड़ा 358 अरब लीटर पहुंचने का अनुमान है। डेटा सेंटर्स का कई उन जिलों में विस्तार हो रहा है, जो पहले से पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फिलहाल डेटा सेंटरों में पानी और बिजली के उपयोग को लेकर अनिवार्य पर्यावरण संरक्षण मानक या अनिवार्य रिपोर्टिंग संबंधी नियम मौजूद नहीं हैं।

अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि जैसी अमेरिकी और रिलायंस एवं अडानी ग्रुप जैसी भारतीय कंपनियां डेटा सेंटर्स के निर्माण से जुड़ी हुई हैं। आशंका है कि इनके रसूख को देखते हुए पानी और बिजली से संबंधित सख्त नियम बनाने को लेकर सरकार कतराएगी, जिसका भविष्य पर बहुत खराब असर होगा। गौरतलब है कि क्लोज्ड-लूप लिक्विड कूलिंग, इमर्सन कूलिंग और 45 डिग्री सेल्सियस लिक्विड कूलिंग जैसे सिस्टम आज मौजूद हैं, जिनसे डेटा सेंटर्स में पानी की जरूरत घट सकती है। अतः डेटा सेंटर्स में इनका इस्तेमाल अनिवार्य करने के नियम सरकार को बनाने चाहिए। पानी के दोबारा इस्तेमाल की अनिवार्यता भी लागू की जानी चाहिए। किसी नए डेटा सेंटर को मंजूरी पानी के वैकल्पिक इंतजाम और जल ऑडिट की शर्त के साथ ही दी जानी चाहिए।

ब्लॉग

बुर्कीना ने फ्रांस से संबंध तोड़े

डॉ. सुधीर सक्सेना

पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र बुर्कीना फासो ने फ्रांस से अपने दौत्य-संबंध तोड़ने का ऐलान किया है। कभी फ्रांस का उपनिवेश रहे बुर्कीना की इस कार्रवाई को बुर्कीना फासो की कठोर कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच यह भी स्पष्ट हो गया है कि बुर्कीना में लोकतंत्र दूर की कौड़ी है और उसे लंबे समय तक फौजी जुंता के अधीन रहना होगा। गत वर्ष के युद्ध में पश्चिमी अफ्रीकी ब्लॉक से संबंध विच्छेद के उपरांत बुर्कीना ने पड़ोसी राष्ट्रों नाइजर और माली के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर मस्क्वा-बीजिंग धुरी की ओर पींगे बढ़ाई हैं और हाल में उसकी रूस पर सामरिक निर्भरता बढ़ी है। गौरतलब है कि बुर्कीना, माली और नाइजर पिछले करीब एक दशक इस्लामी उग्रपंथियों की घुसपैठ से जूझ रहे हैं और उनसे मुकाबले के लिये रूसी सहायता पर निर्भर हैं। फ्रांस से इन देशों के रिश्तों में तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है और अब नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने और बुर्कीना के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ आचरण का आरोप मढ़कर बुर्कीना ने जुमे के रोज़ फ्रांस से राजनयिक संबंध तोड़ लिये हैं।

बुर्कीना फासो छोटा सा अफ्रीकी राष्ट्र है विशालकाय अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिमोत्तर में स्थित भू-आवेष्टित 2.47 लाख वर्ग किमी का लगभग 2.4 करोड़ की आबादी का देश। 65 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है और वह विश्व के चुनींदा निर्धनतम राष्ट्रों में शुमार है। फ्रांस की औपनिवेशक दासता से मुक्त हुये इसे लगभग कुछ दहाइयां ही बीतीहैं और प्रारंभिक लोकतंत्र के बाद वहां तख्तापलट का इतिहास रहा है। वहां आतंकवादी समूह सक्रिय हैं और आर्थिक विकास के पैमाने पर वह बहुत निचली पायदान पर है। यही बुर्कीना फासो इन दिनों विश्वव्यापी सुर्खियों में है और उसकी सुर्खियों में आने का सबब हैं वहां के 38 वर्षीय युवा राष्ट्रपति इब्राहीम ट्रओरे, जो लगभग चार वर्ष पूर्व कू-दे-ता से सत्ता में आये थे। अपनी रीति और नीति से टूओरे पैन-अफ्रीका या अफ्रीकी-अस्मिता के प्रतीक बनकर उभरे हैं। जाहिर है कि वह योरोप और अमेरिका के धनीमानी राष्ट्रों और निओ-इंपीरियालिस्ट ताकतों की आंखों में किरकिरी बनकर खड़क रहे हैं। बिलाशक अपने दुस्साहसिक फैसलों से उन्होंने अमेरिका और फ्रांस जैसे महाबली राष्ट्रों को चुनौती दे डाली है।

कभी अपर वोल्टा के नाम से ज्ञात बुर्कीना सन 1896 में फ्रांसीसी दासता के जुएं तले आया। सन 1958 में स्वशासन के हक के बाद इसे सन 1960 में आजादी मिली। इसके बाद का इतिहास अस्थिरता, अकाल, दुर्भिक्षों, तखतापलट और भ्रष्टाचार की गाथा है। सन 1966, 80, 83 और 87 तथा फिर सन 2022 में दो बार कूदे तो हुये। तख्तापलट के विफल प्रयास सन 1989, 2015 और 2023 में भी देखने को मिली। इनमें उल्लेखनीय रहा सन 1983 में सत्त में आये थॉमस संकारा का कार्यकाल। संकारा पहले राष्ट्राध्यक्ष थे, जिन्होंने बुर्किना फासो को सुधारों और विकास की राह पर बढ़ाया। सामाजिक-आर्थिक, सुधारों के तहत उन्होंने साक्षरता अभियान, भूमि पुर्नवितरण, 20 लाख से अधिक बच्चों का टीकाकरण, रेल और सड़क निर्माण, सबको शिक्षा जैसी योजनाएं लागू कीं। उन्होंने महिलाओं का खतना, बलात विवाह और बहु विवाह पर पाबंदी लगाई, मगर सन 1987 में ब्लेस कोम्पाओरे के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांति में उनका तख्ता पलट कर उनकी हत्या कर दी गयी। ब्लेस की तानाशाही का 31 अक्टूबर 2014 को अंत हुआ, लेकिन उसके बाद बुर्किना अग्रवादी इस्लामी गुटों की घुसपैठ और हिंसा में डूब गया, जिसमें दस लाख से अधिक बुर्कीनाबे विस्थापित हुये।

फ्रेंचकाल में अपर वोल्टा के तौर पर ज्ञात राष्ट्र को बुर्किना फासो नाम थॉमस संकरा की देन है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईमानदारों की धरती। टूओरे की पहल पर फ्रेंच फौजियों को निष्कासित कर तीनों उक्त देशों के रंगरूटो को कानून और सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। हालात का एहसास इससे हो सकता है कि अमेरिका समेत अनेक देशों ने सैलानियों से बुर्कीनो के अंदरूनी भागों की यात्रा नहीं करने को कहा है। देश में यातायात और संचार साधन अत्यल्प हैं। दक्षिण अफ्रीका, माली और घाना के बाद बुर्कीना अफ्रीका का चौथा प्रमुख स्वर्ण उत्पादक राष्ट्र है। सोना, कपास और तिलहन वहां की मुख्य निर्यात वस्तुएं हैं। इनका उत्पादन बढ़ाने के उपक्रमों में तेजी आई है। वैसे बुर्कीनों जवाहरतों का भी निर्यात करता है और वहां के पारंपरिक हस्तशिल्प की विश्व बाजार में अच्छी मांग व प्रतिष्ठा है। टूओरे अब इन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही अधोसंरचना के विकास पर जोर दे रहे हैं।

इसमें शक नहीं संकारा टूओरे के आदर्श हैं और वह उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। संकारा ऐसी शख्सियत थे, जिसने मर्सिडीज की बेड़ा बेचकर सस्ती रेनोल्ट को चुना था। उन्होंने अफसरों के वेतन में कटौती कर उनके प्रथम श्रेणी हवाई टिकट और शोफरों के पर पाबंदी लगा दी थी। वह विदेशी वित्त के विरोधी थे और कहते थे कि ही हू फीड्स यू, कंट्रोल्स यू। अफ्रीका केचेक्वेरा कहे गये संकारा अफ्रीकी राष्ट्रों की एकजुटता चाहते थे, ताकि अफ्रीका का उद्धार हो और वह पश्चिम की गुलामी से मुक्त हो। उन्हें क्यूबा का मॉडेल पसंद था। उन्होंने राजधानी क्वागादोगू में फौज के प्रोवीजन स्टोर को जनसामान्य के लिए देश के पहले सुपर मार्केट में तब्दील कर दिया था। उनके दफ्तर में एयर कंडीशनर नहीं था और वह सिर्फ 450 डालर वेतन लेते थे। उनके पास सिर्फ एक कार, चार बाइक, तीन गिटार, एक रेफ्रीजरेटर और एक टूटा फ्रीजर था। वह कुशल गिटारवादक थे। बिना अंगरक्षकों के वह जॉगिंग पर निकल जाते थे। बुर्कीना का राष्ट्रगीत उन्होंने ही लिखा था। सार्वजनिक दफ्तरों में अपना चित्र नहीं लटकाने पर पूछे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि हमारे यहां सात मिलियन संकारा हैं।

आज पूरा बुर्कीना उन्हीं संकारा को याद कर रहा है। सन 2019 में राजधानी में उसी ठोर उनकी प्रतिमा लगी, जहां उनकी हत्या हुई थी। मुखाकृति नहीं मिलने से अगले वर्ष नयी प्रतिमा स्थापित की गयी। टूओरे के सत्ता में आने के बाद सन 2023 में उन्हें 'हीरो ऑफ द नेशन घोषित किया गया। अक्टूबर सन 2023 में ही राजधानी के बुल्वार चार्ल्स द गाल का नाम बदलकर बुल्वार कैप्टेन थॉमस संकारा कर दिया गया। इस बीच क्यूबा ने संकारा को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जोसे मार्टी से विभूषित किया।

उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की बुर्कीना में सौ मस्जिदें बनाने की पेशकश यह कहकर ठुकरा दी है कि हमें मस्जिदों की नहीं, वरन स्कूल-कालेजों, अस्पतालों और कल कारखानों की जरूरत है। इसमें शक नहीं कि युवा टूओरे संकारा के जूतों में पांब डाल चुके हैं।

घटनाक्रम से स्पष्ट है कि बुर्कीना का ताजा कदम फ्रांस, अमेरिका और योरोपीय देशों को पसन्द नहीं आयेगा। फ्रेंच सैनिक टुकड़ियों को इलाके से पहले ही निष्कासित किया जा चुका है। यह भी साफ है कि बुर्कीना में लोकतंत्र की बहाली के कोई आसार नहीं हैं।

टओरे ने दो टूक कह दिया है कि लोकतंत्र हमारे लिये नहीं है। डेमोक्रैसी इज नॉट फार अस। लीबिया का उदाहरण देते हुये उन्होंने कहा कि अफ्रीकी राष्ट्रों में लोकतंत्र की स्थापना का अर्थ है रक्तपात। हमारा रास्ता अलग है और हमें सुदृढ़ आर्थिकी, अधिक मेहनत और मजबूत फौज की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि जुंता ने सन 2024 में लोकतंत्र की बहाली का वायदा किया था, किंतु जनवरी, सन 24 से सभी राजनीतिक दलों को भंग कर उसने आगामी पांच वर्षों के लिये सत्ता पर फौज के काबिज रहने का ऐलान कर दिया। इस बीच पश्चिमी सूत्रों ने बुर्कीना में जुंता काल में करीब 1800 निर्दोष नागरिकों के मारे जाने का आरोप लगाया है, जिसका जुंता ने खंडन किया है।

कंपोजिट विद्यालय के बाहर ई-रिक्शा की टक्कर से कक्षा एक की छात्रा की मौत, चालक फरार

सुलतानपुर। कोतवाली देहात क्षेत्र के पखरौली स्थित कंपोजिट विद्यालय के मुख्य गेट के बाहर मंगलवार को ई-रिक्शा की टक्कर से कक्षा एक की छात्रा की मौत हो गई। हादसे के बाद विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार कोतवाली देहात क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय पखरौली में मंगलवार सुबह करीब 11.15 बजे कक्षा एक की छह वर्षीय छात्रा अश्वनी, पुत्री दिनेश कुमार, विद्यालय के गेट के सामने सामान से लदे एक ई-रिक्शा की चपेट में आ गई। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। विद्यालय के शिक्षक तत्काल उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही विद्यालय में अफरा-तफरी मच गई।

जिस बीवी को समझता था IAS अफसर, वो निकली शातिर ठग

पुलिस ने भेजा जेल, बरेली के अभिषेक के साथ कैसे हुआ धोखा

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फरीदपुर थाना क्षेत्र से धोखाधड़ी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिस पर खुद को आईएएस अधिकारी बताकर शादी करने, फर्जी दस्तावेजों के जरिए युवक को विश्वास में लेने और बाद में उससे 40 लाख रुपये की मांग करने का आरोप है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला को बदायूं से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, फरीदपुर क्षेत्र के पचौमी गांव निवासी अभिषेक ने करीब 15 दिन पहले अपनी पत्नी साधना और उसके मायके पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में अभिषेक ने बताया कि शादी से पहले साधना ने खुद को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का अधिकारी बताया था।

आरोप है कि उसने अपने दावे को सही साबित करने के लिए कई फर्जी प्रमाणपत्र, सम्मान पत्र और अन्य दस्तावेज दिखाए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी उसने ऐसी तस्वीरें और पोस्ट साझा कर रखी थीं, जिससे लोग उसे प्रशासनिक अधिकारी समझें। इन सब बातों पर भरोसा कर अभिषेक ने साधना से शादी कर ली।

शादी के बाद खुली सच्चाई, शुरू हुआ विवाद

अभिषेक का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद उसे पत्नी की असलियत का पता चला। जांच-पड़ताल में सामने आया कि वह आईएएस अधिकारी नहीं है और उसने शादी के लिए अपनी पहचान के बारे में झूठ बोला था। इसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और रिश्तों में तनाव बढ़ता चला गया।

40 लाख रुपये की मांग, परिवार को दी धमकी

पीड़ित पति का आरोप है कि सच्चाई सामने आने के बाद साधना ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह लगातार 40 लाख रुपये देने का दबाव बनाने लगी। रुपये नहीं देने पर झूठे मुकदमों में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी गई। अभिषेक ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि साधना ने सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके माता-पिता, भाई और बहनों को भी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इन धमकियों से पूरा परिवार भय और मानसिक तनाव में रहने लगा। इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।

बदायूं से गिरफ्तारी, कोर्ट ने भेजा जेल

मामला दर्ज होने के बाद फरीदपुर पुलिस ने जांच शुरू की और बदायूं में दबिश देकर साधना को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे फरीदपुर लाकर पूछताछ की गई और फिर कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

फरीदपुर के क्षेत्राधिकारी (सीओ) संदीप सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान महिला ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, आपराधिक धमकी और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या महिला ने इसी तरह किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी धोखाधड़ी की है।

चर्चित माता प्रसाद पाण्डेय हत्याकांड में दो आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत

सुलतानपुर। कुड़वार थाना क्षेत्र के पूरे बेनी माधव निवासी माता प्रसाद पाण्डेय हत्याकांड में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच से दो आरोपियों को जमानत मिलने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जानकारी के अनुसार, 25 मार्च 2026 को प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद को लेकर माता प्रसाद पाण्डेय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

बताया जाता है कि इस मामले का मुख्य प्रत्यक्षदर्शी मृतक का पुत्र अवनीश पाण्डेय है। पुलिस जांच में ग्राम रूपापुर निवासी रमेश मौर्य, उनके पुत्र अनुराग मौर्य तथा सुरेंद्र कुमार शर्मा को नामजद किया गया था। बाद में विवेचना के दौरान कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के नाम भी सामने आए। मामले में आरोपियों की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुखदेव सिंह ने पैरवी की।

बसपा नेता की हत्या के बाद बना मोस्ट वांटेड, कौन था 1 लाख का इनामी मुस्तफिजुल

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सोमवार देर रात एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक लाख रुपये के इनामी बदमाश मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू का एनकाउंटर कर दिया। रामनगर करजहां इलाके में रात करीब 11:15 बजे हुई इस मुठभेड़ में दोनों ओर से करीब आधे घंटे तक फायरिंग चली। पुलिस के अनुसार, मुस्तफिजुल को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुस्तफिजुल उर्फ बाबू गोरखपुर से कुशीनगर की ओर बाइक से जा रहा है। सूचना के आधार पर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया।

पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वह बाइक लेकर भागने लगा। पीछा किए जाने पर उसने पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं।

मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुस्तफिजुल के पैर और आंख के पास गोली लगी। घायल बदमाश को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया।

बसपा नेता की हत्या के बाद बना था मोस्ट वांटेड

मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। करीब चार वर्ष पहले उसने बसपा नेता कलामुद्दीन उर्फ कमालू की हत्या कर दी थी। कलामुद्दीन बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके थे। इस हत्याकांड के बाद से मुस्तफिजुल पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था और उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

गुजरात से गिरफ्तारी के बाद ट्रेन से हो गया था फरार

पुलिस ने दिसंबर 2024 में मुस्तफिजुल को गुजरात से गिरफ्तार किया था। उसे आजमगढ़ लाया जा रहा था, तभी महाराष्ट्र के अमरावती रेलवे स्टेशन के पास उसने शौचालय जाने का बहाना बनाया और चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। वह बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था, जिससे उसकी गिरफ्तारी चुनौती बनी हुई थी। News (11)

2003 में चोरी से शुरू हुआ अपराध का सफर

मुस्तफिजुल का आपराधिक रिकॉर्ड दो दशक से अधिक पुराना था। उसके खिलाफ पहला मुकदमा वर्ष 2003 में आजमगढ़ के मेहनगर थाने में चोरी के आरोप में दर्ज हुआ था। इसके बाद वर्ष 2008 में हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर मामलों में उसका नाम सामने आया। वर्ष 2011 में फिर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ और वह फरार हो गया।

वर्ष 2012 में उसके खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में अदालत के आदेश पर उसकी संपत्ति भी कुर्क की गई थी। वर्ष 2021 में बसपा नेता की हत्या के मामले में उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, पुलिस हिरासत से फरार होने सहित कुल 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इनमें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, हरदोई और महाराष्ट्र में दर्ज मामले भी शामिल हैं।

मुठभेड़ स्थल से हथियार और बाइक बरामद

पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से 32 बोर की एक पिस्टल, एक मोटरसाइकिल और बड़ी संख्या में खाली खोखे बरामद किए हैं। पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुस्तफिजुल लंबे समय से कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ था और उसकी तलाश कई राज्यों की पुलिस कर रही थी।

वरिष्ठ पत्रकार के .के . तिवारी का निधन, पत्रकारिता और स्वास्थ्य विभाग में शोक

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। जिले के वरिष्ठ पत्रकार एवं जिला क्षय रोग (टीबी) विभाग में एसटीएलएस (सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर) के पद पर कार्यरत के.के. तिवारी का मंगलवार तड़के निधन हो गया। उनके निधन से पत्रकारिता जगत, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार तड़के करीब तीन बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उन्हें तत्काल स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज के आकस्मिक चिकित्सा कक्ष लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान सुबह करीब चार बजे चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।मृतक पत्रकार कुड़वार विकास खंड के खादर बसंतपुर ग्राम पंचायत के निवासी थे ।

के.के. तिवारी लंबे समय तक हिन्दुस्तान समाचार पत्र में जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत रहे। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न समाचार संस्थानों में भी अपनी सेवाएं दीं। निष्पक्ष, निर्भीक और जनसरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता के कारण उन्होंने जिले में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई थी। पत्रकारिता के साथ-साथ वह कई वर्षों से जिला क्षय रोग विभाग में एसटीएलएस के पद पर कार्यरत थे। अपने कर्तव्यनिष्ठ, सरल एवं मिलनसार व्यक्तित्व के कारण वह विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन के बीच समान रूप से सम्मानित थे। उनके निधन का समाचार मिलते ही पत्रकारों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों तथा शुभचिंतकों ने गहरा शोक व्यक्त किया। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। दोपहर में कुड़वार घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके इकलौते पुत्र नीतीश तिवारी ने नम आंखों से अपने पिता को मुखाग्नि दी। वरिष्ठ पत्रकार के.के. तिवारी के निधन को जिले की पत्रकारिता और स्वास्थ्य विभाग के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन की मांग, शिक्षामित्रों ने बीएसए कार्यालय में सौंपा ज्ञापन

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। टेट/सीटेट उत्तीर्ण शिक्षामित्रों ने सोमवार को माननीय हाईकोर्ट के आदेश एवं अपर राज्य परियोजना निदेशक के निर्देशों का अनुपालन न होने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। शिक्षामित्र शिक्षक पात्रता संघ की जिलाध्यक्ष नीतू द्विवेदी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने न्यायालय के आदेशों का शीघ्र पालन सुनिश्चित कराने की मांग की।

बीएसए की अनुपस्थिति में ज्ञापन जिला समन्वयक (डीसी) अपूर्वा त्रिपाठी ने प्राप्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि 17 अप्रैल 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवधेश कुमार श्रीवास्तव एवं 419 अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में आदेश पारित किया था। इसके अनुपालन में 19 जून 2026 को अपर राज्य परियोजना निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए थे। इसके बावजूद अब तक आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जिससे टेटध्सीटेट उत्तीर्ण याची शिक्षामित्रों को प्रशासनिक एवं सेवा संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षामित्रों ने ज्ञापन के माध्यम से न्यायालय के आदेशों का तत्काल अनुपालन कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान जिला समन्वयक अपूर्वा त्रिपाठी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि न्यायालय के आदेश एवं विभागीय निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई शीघ्र कराई जाएगी तथा प्रकरण का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में पुष्पा वर्मा, गायत्री वर्मा, वंदना पांडेय, पुष्पा देवी, साधना सिंह, रिंकू वर्मा, नीलम तिवारी, रामलखन, रीता देवी, रमेश यादव, उपमा सिंह, भूमिका सिंह, संजय श्रीवास्तव, शोभावती देवी, रीता वर्मा, पुष्पाबेन यादव, अविनाश श्रीवास्तव सहित अवधेश कुमार श्रीवास्तव एवं 419 अन्य प्रकरण से जुड़े बड़ी संख्या में याची शिक्षामित्र उपस्थित रहे।

लिफ्ट बंद हुई तो भगवान का लिया सहारा ! ग्रेटर नोएडा में 30 मिनट तक फंसी बच्चियां, पढ़ती रहीं हनुमान चालीसा

आर्यावर्त संवाददाता

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाईराइज सोसाइटी में सोमवार रात ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। गैलेक्सी वेगा सोसाइटी की एक लिफ्ट अचानक बीच रास्ते में बंद हो गई, जिसमें चार मासूम बच्चियां करीब 30 मिनट तक फंसी रहीं।

घबराहट और डर के माहौल में बच्चियों ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि भगवान का सहारा लेते हुए लिफ्ट के अंदर ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार रात चार बच्चियां लिफ्ट से अपने फ्लोर पर जा रही थीं। इसी दौरान अचानक लिफ्ट बीच में रुक गई। कुछ पल के लिए लिफ्ट के भीतर अंधेरा भी छा गया, जिससे बच्चियां काफी डर गईं। हालांकि, थोड़ी देर बाद लाइटें दोबारा जल गईं, लेकिन लिफ्ट नहीं चली और बच्चियां अंदर ही फंसी रहीं।

सोसाइटी के लोगों का कहना है कि बच्चियां करीब आधे घंटे तक लिफ्ट में कैद रहीं। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी मदद का इंतजार किया, लेकिन घबराहट के बीच खुद को संभालने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया।

डर के बीच गूंजती रही हनुमान चालीसा

करीब 30 मिनट तक लिफ्ट के अंदर बैठी चारों बच्चियां लगातार हनुमान चालीसा पढ़ती रहीं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी बच्चियां पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करती नजर आ रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोग बच्चियों के साहस और धैर्य की सराहना कर रहे हैं।

कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाली गईं बच्चियां

सूचना मिलने के बाद सोसाइटी के कर्मचारी और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। काफी प्रयास के बाद लिफ्ट का दरवाजा खोला गया और सभी बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी भी बच्ची को शारीरिक चोट नहीं आई, लेकिन वे काफी डरी हुई थीं।

लिफ्टों की हालत पर उठे सवाल

घटना के बाद सोसाइटी के निवासियों ने लिफ्टों के रखरखाव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सोसाइटी में लिफ्ट खराब होने की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन उनका स्थायी समाधान नहीं किया गया। निवासियों का कहना है कि यदि समय रहते लिफ्टों की नियमित जांच और मरम्मत नहीं की गई, तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। सोसाइटी के लोगों ने प्रबंधन से लिफ्टों का तत्काल सुरक्षा ऑडिट कराने और नियमित मेंटेनेंस सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

नोएडा–ग्रेटर नोएडा के लाखों लोगों को मिलेगी जाम से राहत... तिलपता से कंटेनर डिपो तक बनेगा एलिवेटेड रोड

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के बीच सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। ग्रेटर नोएडा की तिलपता क्षेत्र में डीएससी मार्ग पर लगने वाले रोजाना के भीषण जाम से निजात दिलाने के लिए करीब 4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश सेतु निगम इस परियोजना का सर्वे और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार करेगा। डीपीआर के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। आइए जानते हैं कि एलिवेटेड रोड बनने से किन-किन इलाके के लोगों को सीधा फायदा होगा और जाम से कितनी राहत मिलेगी।

जानकारी के मुताबिक तिलपता गोल चक्कर से कंटेनर डिपो तक का यह इलाका लंबे समय से ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या से जूझ रहा है। यहां से दादरी रेलवे ओवरब्रिज, रूपवास बाईपास, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों का भारी दबाव रहता है।

खासकर कंटेनर और अन्य भारी वाहनों के कारण घंटो जाम की स्थिति बनी रहती है। एलिवेटेड रोड बनने के बाद भारी वाहनों का आवागमन ऊपरी मार्ग से कराया जाएगा, जबकि नीचे की सड़क स्थानीय ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। इससे मुख्य सड़क पर दबाव कम होगा और लोगों को लंबे जाम से राहत मिलेगी।

कहां से कहां तक बनेगा एलिवेटेड रोड?

प्राधिकरण के अधिकारी के अनुसार एलिवेटेड रोड की शुरुआत तिलपता गोल चक्कर के पास स्थित पुलिस चौकी से होगी और यह कंटेनर डिपो तक जाएगा। परियोजना की लंबाई करीब 4 किलोमीटर होगी। इस योजना का सर्वे और डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सेतु निगम को सौंपी गई है। इसके लिए प्राधिकरण ने प्रारंभिक भुगतान भी जारी कर दिया है। डीपीआर तैयार होने के बाद तय होगा कि सड़क कितने लेन की होगी और निर्माण पर कुल कितना खर्च आएगा।

एलिवेटेड रोड बनने से क्या होगा फायदा?

परियोजना विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एलिवेटेड रोड बनने के बाद कंटेनर डिपो की ओर से जाने वाले सभी भारी वाहन इसी रास्ते से होकर गुजरेंगे। इससे स्थानीय ट्रैफिक प्रभावित नहीं होगा और रोजाना लगने वाले भीषण जाम में काफी कमी आएगी। मौजूदा सड़क स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए पहले की तरह खुली रहेगी।

वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवी कुमार एनजी ने कहा कि शहर में लगातार ट्रैफिक का दबाब तेजी से बढ़ रहा है। तिलपता गोल चक्कर और कंटेनर डिपो के पास जाम एक बड़ी समस्या बन चुका है। एलिवेटेड रोड बनने से लोगों का सफर आसान होगा, ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली आने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

डीएम के निर्देश पर शारदा सहायक नहर के कुलाबों का होगा कायाकल्प

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। जनपद में किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने शारदा सहायक खंड-16 की बायीं नहर के कुलाबों के कायाकल्प का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर ग्राम सुकरेशिया से वेदहा मार्ग के किनारे स्थित सभी कुलाबों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। योजना के पूरा होने पर लगभग 100 हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि सिंचाई के दायरे में आ जाएगी।

जिला प्रशासन के अनुसार क्षेत्र के किसान लंबे समय से नहर का पानी खेतों तक पर्याप्त मात्रा में न पहुंचने की समस्या से जूझ रहे थे। कुलाबों के कायाकल्प के बाद नहर का पानी आसानी से खेतों तक पहुंचेगा, जिससे सिंचाई व्यवस्था में सुधार होगा, खेती की लागत कम होगी और कृषि उत्पादन बढ़ने की संभावना है। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी निर्माण कार्य शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप कराए जाएं। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी शारदा सहायक खंड-16 के अधिशासी अभियंता शरद कुमार एवं सहायक अभियंता मंगल यादव को सौंपी गई है। दोनों अधिकारियों को कार्य में तेजी लाकर किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय किसानों ने जिला प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि कुलाबों के जीर्णोद्धार से वर्षों पुरानी सिंचाई समस्या का समाधान होगा। समय पर पानी मिलने से फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की निजी सिंचाई संसाधनों पर निर्भरता भी कम होगी। जिलाधिकारी ने किसानों से जल संरक्षण की अपील करते हुए कहा कि सिंचाई पूरी होने के बाद नहर का पानी अनावश्यक रूप से न बहने दें तथा आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करें।

मटर से बनाएं टेस्टी रेसिपीज़, मिनटों में तैयार होगा लाजवाब नाश्ता

मटर एक ऐसी सब्जी है, जिसका इस्तेमाल भारतीय रसोई में कई तरह के व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। इसका हल्का मीठा स्वाद और मुलायम बनावट इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की पसंद बनाते हैं। चाहे सर्दियों का मौसम हो या फ्रोजन मटर का उपयोग, इसे पूरे साल आसानी से डाइट में शामिल किया जा सकता है। यही वजह है कि मटर से कई स्वादिष्ट और झटपट बनने वाले नाश्ते तैयार किए जाते हैं।

मटर में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, आयरन, पोटैशियम और कई जरूरी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। संतुलित मात्रा में इसका सेवन पाचन को बेहतर बनाए रखने, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने, लंबे समय तक पेट भरा रखने और शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने में मदद कर सकता है। साथ ही, इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन इसे संतुलित डाइट का जरूरी हिस्सा बनाते हैं। आइए जानते हैं कि मटर से कौन-से टेस्टी और झटपट नाश्ते बनाए जा सकते हैं और मटर खरीदते, स्टोर करते व पकाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

मटर से बनाएं ये 5 टेस्टी और झटपट नाश्ते

मटर पोहा

पोहा को धोकर अलग रख दें। एक पैन में राई, करी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज भूनें। इसमें उबले हुए मटर और हल्दी डालें, फिर पोहा मिलाकर कुछ मिनट पकाएं। ऊपर से नींबू का रस और हरा धनिया डालें। यह फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हल्का और पौष्टिक नाश्ता है।

मटर चीला

बेसन के घोल में उबले हुए मटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और मसाले मिलाएं। इस घोल को तवे पर फैलाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर नाश्ता है, जो लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद कर सकता है।

मटर सैंडविच

उबले हुए मटर को हल्का मैश करके उसमें प्याज, शिमला मिर्च, काली मिर्च और थोड़ा पनीर मिलाएं। इस मिश्रण को गेहूं या मल्टीग्रेन ब्रेड के बीच भरकर तवे या सैंडविच मेकर में सेक लें। यह स्वादिष्ट नाश्ता प्रोटीन, फाइबर और विटामिन का अच्छा सोर्स बन सकता है।

मटर कटलेट

उबले हुए मटर में उबले आलू, गाजर, अदरक, हरा धनिया और मसाले मिलाकर टिक्की बना लें। इन्हें हल्के तेल में तवे पर सेंकें या एयर फ्रायर में तैयार करें। यह बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम नाश्ता है, जो फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है।

मटर पराठा

उबले हुए मटर को मैश करके उसमें हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और मसाले मिलाएंम इस मिश्रण को गेहूं के आटे की लोई में भरकर पराठा बेलें और तवे पर हल्का घी लगाकर सेंक लें। दही या चटनी के साथ परोसा गया यह पराठा स्वादिष्ट होने के साथ पेट भरने वाला विकल्प है।

मटर खरीदते, स्टोर करते और पकाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मटर खरीदते समय हमेशा ताजी, हरी और भरी हुई फलियां चुनें। अगर पैक्ड या फ्रोजन मटर खरीद रहे हैं, तो पैकेट की एक्सपायरी डेट जरूर जांचें। ताजी मटर को फ्रिज में एयरटाइट डिब्बे या छिद्र वाले बैग में स्टोर करें, ताकि उसकी ताजगी बनी रहे। लंबे समय तक रखने के लिए मटर को हल्का उबालकर फ्रीज भी किया जा सकता है।

मटर को बहुत देर तक पकाने से इसके कुछ पोषक तत्व, खासकर विटामिन सी, कम हो सकता हैं। इसलिए इसे मध्यम आंच पर जरूरत के अनुसार ही पकाएं। इस्तेमाल करने से पहले मटर को अच्छी तरह धो लें और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। संतुलित मात्रा में मटर को नियमित डाइट में शामिल करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।

प्रेग्नेंसी में क्यों बढ़ जाती है कैल्शियम की जरूरत

प्रेग्नेंसी के दौरान खानपान और पोषक तत्वों का खास ध्यान रखना जरूरी होता है। डॉक्टर भी इस समय कैल्शियम लेने की सलाह देते हैं। आइए जानते हैं कि प्रेग्नेंसी में कैल्शियम की जरूरत क्यों बढ़ जाती है और यह मां व शिशु के लिए क्यों जरूरी है।

प्रेग्नेंसी हर महिला के जीवन का एक अहम चरण होता है। इस दौरान मां के शरीर में कई शारीरिक और हॉर्मोनल बदलाव होते हैं, इसलिए खानपान का विशेष ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। संतुलित डाइट न केवल प्रग्नेंट महिला की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे के सामान्य विकास के लिए भी जरूरी भूमिका निभाती है। इसी वजह से डॉक्टर प्रेग्नेंसी के दौरान जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेने की सलाह देते हैं।

कैल्शियम ऐसा ही एक आवश्यक मिनरल है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने के साथ-साथ मांसपेशियों, नसों और हार्ट के सामान्य कार्यों के लिए भी जरूरी होता है। प्रेग्नेंसी के दौरान कैल्शियम की कमी होने पर मां की हड्डियां कमजोर पड़ सकती हैं और कुछ मामलों में स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए इस पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा लेना जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं कि प्रेग्नेंसी में कैल्शियम की जरूरत क्यों बढ़ जाती है, इसे पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए और सप्लीमेंट लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

प्रेग्नेंसी में कैल्शियम की जरूरत क्यों बढ़ जाती है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, प्रेग्नेंसी के दौरान कैल्शियम मां और गर्भ में पल रहे शिशु, दोनों के लिए जरूरी पोषक तत्व है। यह शिशु की हड्डियों और दांतों के सामान्य विकास में अहम भूमिका निभाता है। अगर प्रेग्नेंट महिला को भोजन से पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता, तो शरीर शिशु की जरूरत पूरी करने के लिए मां की हड्डियों में मौजूद कैल्शियम का उपयोग कर सकता है।

WHO यह भी बताता है कि जिन क्षेत्रों में महिलाओं के डाइट में कैल्शियम की मात्रा कम होती है, वहां प्रेग्नेंसी के दौरान डॉक्टर की सलाह पर कैल्शियम सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं। इससे प्री-एक्लेम्पसिया यानी हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी गंभीर गर्भावस्था जटिलता का खतरा कम करने में भी मदद मिल सकती है। इसलिए प्रेग्नेंसी में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा लेना और डॉक्टर की सलाह के अनुसार डाइट या सप्लीमेंट का पालन करना जरूरी माना जाता है।

प्रेग्नेंसी में कैल्शियम की जरूरत पूरी करने के लिए क्या खाएं?

कैल्शियम की जरूरत पूरी करने के लिए डाइट में दूध, दही, पनीर और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा रागी, तिल, सोया से बनी चीजें, टोफू, बादाम, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक लेकिन संतुलित मात्रा में और फोर्टिफाइड खाने की चीजें भी कैल्शियम के अच्छे सोर्स माने जाते हैं।

संतुलित डाइट लेने से शरीर को कैल्शियम के साथ अन्य जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं। अगर सिर्फ भोजन से जरूरत पूरी न हो रही हो, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार सप्लीमेंट लिया जा सकता है।

कैल्शियम सप्लीमेंट लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

कैल्शियम सप्लीमेंट हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। निर्धारित मात्रा से अधिक सप्लीमेंट लेने से बचें। अगर आयरन और कैल्शियम दोनों सप्लीमेंट लेने हों, तो उन्हें एक साथ लेने के बजाय डॉक्टर द्वारा बताए गए अंतराल पर लें, क्योंकि दोनों के एब्जॉर्पशन पर असर पड़ सकता है।

सप्लीमेंट के साथ पर्याप्त पानी पिएं और नियमित जांच के दौरान डॉक्टर से अपनी पोषण संबंधी जरूरतों पर चर्चा करते रहें। संतुलित डाइट के साथ ही सप्लीमेंट का सेवन करना अधिक उपयुक्त माना जाता है।

ब्रोकली से सिर्फ सलाद नहीं, ट्राई करें ये 5 स्वादिष्ट और हेल्दी डिश

ब्रोकली पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी है, जिसे ज्यादातर लोग सलाद के रूप में खाते हैं। आइए जानते हैं कि ब्रोकली से सलाद के अलावा कौन-सी 5 टेस्टी और आसान डिश तैयार की जा सकती हैं।

आजकल लोग अपनी डाइट में ऐसी सब्जियां शामिल करना पसंद कर रहे हैं, जो स्वाद के साथ-साथ भरपूर पोषण भी दें। ब्रोकली भी ऐसी ही एक हरी सब्जी है, जिसे हेल्दी लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा माना जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर सलाद के रूप में किया जाता है। हल्के स्वाद और कुरकुरी बनावट की वजह से यह बच्चों और बड़ों, दोनों की डाइट में आसानी से शामिल की जा सकती है।

ब्रोकली में विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, फाइबर, पोटैशियम और कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। संतुलित मात्रा में इसे डाइट में शामिल करने से इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने, पाचन को बेहतर बनाने, हड्डियों की सेहत को सपोर्ट करने और शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिल सकती है। साथ ही, इसमें कैलोरी कम और फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए इसे संतुलित डाइट का जरूरी हिस्सा माना जाता है। आइए जानते हैं कि ब्रोकली से कौन-सी स्वादिष्ट और हेल्दी डिश बनाई जा सकती हैं और ब्रोकली खरीदते, स्टोर करते व पकाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

ब्रोकली से बनाएं ये 5 टेस्टी और हेल्दी डिश

ब्रोकली सूप

ब्रोकली, प्याज और लहसुन को हल्का उबाल लें। फिर इन्हें पीसकर दोबारा कुछ मिनट पकाएं। चाहें तो इसमें थोड़ा दूध या काली मिर्च मिला सकते हैं। यह हल्का और पौष्टिक सूप विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स है, जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है।

ब्रोकली कटलेट

उबली हुई ब्रोकली में उबले आलू, गाजर, ओट्स या ब्रेडक्रम्ब्स और हल्के मसाले मिलाकर कटलेट तैयार करें। इन्हें तवे पर कम तेल में सेंकें या एयर फ्रायर में पकाएं। यह स्वादिष्ट स्नैक फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है तथा बच्चों के लिए भी अच्छा विकल्प बन सकता है।

ब्रोकली पनीर

ब्रोकली और पनीर के टुकड़ों को प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन और हल्के मसालों के साथ पकाएं। इसे गेहूं की रोटी या मल्टीग्रेन रोटी के साथ परोसें। इस डिश से पनीर का प्रोटीन और कैल्शियम तथा ब्रोकली के विटामिन सी और फाइबर का लाभ मिल सकता है।

ब्रोकली पराठा

ब्रोकली को कद्दूकस करके उसमें हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और हल्के मसाले मिलाएं। इस मिश्रण को गेहूं के आटे की लोई में भरकर पराठा बेलें और तवे पर हल्का घी लगाकर सेंक लें। यह स्वादिष्ट नाश्ता फाइबर, विटामिन और एनर्जी का अच्छा सोर्स हो सकता है।

ब्रोकली पास्ता

होल व्हीट पास्ता को उबाल लें। एक पैन में ब्रोकली, शिमला मिर्च, प्याज और लहसुन को हल्का भूनें, फिर पास्ता और अपनी पसंद की सॉस मिलाकर कुछ मिनट पकाएं। यह डिश कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और विटामिन का अच्छा मिश्रण है, जो बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आ सकती है।

ब्रोकली खरीदते, स्टोर करते और पकाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

ब्रोकली खरीदते समय ऐसी ब्रोकली चुनें, जिसके फूल गहरे हरे रंग के, सख्त और ताजे हों। पीले या मुरझाए हुए फूलों वाली ब्रोकली लेने से बचें। इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह धो लें और जरूरत के अनुसार ही काटें। ब्रोकली को बहुत देर तक उबालने या तेज आंच पर अधिक समय तक पकाने से इसके कुछ पोषक तत्व, खासकर विटामिन सी, कम हो सकता है।

इसलिए इसे हल्का स्टीम या कम समय तक पकाना बेहतर माना जाता हैएम ताजी ब्रोकली को फ्रिज में एयरटाइट या छेद वाले बैग में स्टोर करें और कुछ दिनों के भीतर उपयोग कर लें, ताकि इसका स्वाद और पोषण बना रहे।

दिल्ली ईवी नीति पर क्रिसिल की चिंता: दोपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक बदलाव सबसे बड़ी चुनौती

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को लेकर क्रिसिल रेटिंग्स ने दोपहिया वाहन श्रेणी को सबसे बड़ी चुनौती बताया है। सूत्रों का कहना है कि नीति के अनुसार अप्रैल 2028 से पारंपरिक ईंधन इंजन वाले नए दोपहिया वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाने का प्रस्ताव है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में दिल्ली में इस श्रेणी में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी केवल 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ऐसे में उद्योग को बहुत कम समय में बड़े बदलाव के लिए तैयार होना होगा।

क्रिसिल रेटिंग्स की निदेशक पूनम उपाध्याय ने कहा कि अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के पंजीकरण की व्यवस्था वाहन निर्माताओं को इलेक्ट्रिक उत्पादों, उत्पादन क्षमता और वितरण नेटवर्क में निवेश बढ़ाने का स्पष्ट संकेत देती है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निकट भविष्य में आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाले वाहन पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे और उनकी बाजार में प्रासंगिकता बनी रहेगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के दोपहिया वाहन बाजार की भविष्य की वृद्धि काफी हद तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उद्योग की तैयारी पर निर्भर करेगी। विभिन्न वाहन श्रेणियों पर इस नीति का प्रभाव अलग-अलग होगा। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल दोपहिया पंजीकरण लगभग 25 प्रतिशत बढ़कर 5.7 लाख इकाई तक पहुंचने का अनुमान है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी केवल 7.3 प्रतिशत रहेगी।

प्रस्तावित नीति के अनुसार अप्रैल 2028 से सभी नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। इसके लिए पहले वर्ष प्रति वाहन 30 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसे अगले दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा।

पूनम उपाध्याय ने कहा कि नीति में पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने पर मिलने वाले लाभ तथा करों में छूट जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। लेकिन जैसे-जैसे सरकारी वित्तीय सहायता कम होगी, वैसे-वैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत, परिचालन लागत और स्वामित्व की कुल लागत उपभोक्ताओं के निर्णय में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

क्रिसिल के अनुसार चारपहिया निजी वाहनों के मामले में बदलाव अपेक्षाकृत धीमा रहेगा। नई नीति में निजी कारों के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण अनिवार्य नहीं किया गया है, बल्कि प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया गया है। इसलिए मध्यम अवधि तक पारंपरिक इंजन वाले वाहन बाजार में बने रहेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति वाहन की कीमत, चार्जिंग सुविधाओं और विभिन्न मॉडलों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

वित्त वर्ष 2025-26 में दिल्ली में लगभग दो लाख चारपहिया वाहनों का पंजीकरण हुआ, जिनमें लगभग 77 हजार इलेक्ट्रिक वाहन और करीब 52 हजार हाइब्रिड वाहन शामिल थे। प्रस्तावित नीति के तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले सभी इलेक्ट्रिक चारपहिया यात्री वाहनों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है।

क्रिसिल का मानना है कि सबसे तेज बदलाव तीनपहिया वाहन श्रेणी में देखने को मिलेगा। प्रस्ताव के अनुसार 1 जनवरी 2027 से नए तीनपहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। हालांकि इसकी सफलता पर्याप्त वाहन उपलब्धता, आसान वित्तपोषण, चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी बदलने की सुविधाओं के विस्तार पर निर्भर करेगी।

वित्त वर्ष 2025-26 में दिल्ली में कुल 55,700 तीनपहिया वाहनों का पंजीकरण हुआ, जिनमें लगभग दो-तिहाई इलेक्ट्रिक वाहन थे।

क्रिसिल रेटिंग्स का कहना है कि दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति देश में राज्य स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सबसे महत्वाकांक्षी पहलों में से एक है। पंजीकरण संबंधी नियमों, वित्तीय प्रोत्साहनों और पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने जैसे उपायों के माध्यम से सरकार राजधानी में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को तेजी से बढ़ावा देना चाहती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस लक्ष्य की सफलता उद्योग की तैयारी, उपभोक्ताओं की स्वीकार्यता और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के समय पर विकास पर निर्भर करेगी।

सस्ती होंगी जगुआर लैंड रोवर जैसी लक्जरी गाड़ियां, ब्रिटेन से आने वाली कारों पर सिर्फ 10 प्रतिशत लगेगा आयात शुल्क

सरकार ने ब्रिटेन से कार और वाहन आयात होने पर रियायती शुल्क फायदों पर अधिसूचना जारी की। दरअसल, भारत-ब्रिटेन समग्र आर्थिक एवं व्यापार समझौता बुधवार से लागू होगा।

इस समझौते में 15 साल की अवधि में शुल्क दर कोटे (टीआरक्यू) में चरणबद्ध ढंग से बदलाव किए जाएंगे। साथ ही भारत के घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण पारिस्थितिकीतंत्र को भी सुरक्षित रखा जाएगा। समझौते के अनुसार भारत वाहनों पर आयात शुल्क को लगभग 110 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर देगा और यह कोटा दोनों पक्षों पर लागू होगा।

उद्योग के सूत्रों का कहना है कि इस समझौते से भारत के प्रीमियम वाहन बाजार में तुरंत कोई रुकावट आने की उम्मीद नहीं है जबकि देश का तेजी से बढ़ता घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण पारिस्थितिकीतंत्र सुरक्षित रहेगा।

यह भी माना जा रहा है कि लक्जरी खंड में धीरे-धीरे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जैसे-जैसे शुरुआती पांच वर्षों में शुल्क घटकर 10 प्रतिशत के स्तर पर आएगा। इससे ब्रिटेन से आयात की जाने वाली गाड़ियां मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी कंपनियों के स्थानीय स्तर पर असेंबल किए गए लक्जरी मॉडलों के मुकाबले ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकती हैं। इससे जगुआर लैंड रोवर जैसी कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद है।

ऑटोमोटिव इंटेलिजेंस फर्म जेएटीओ डायनामिक्स के प्रेसिडेंट रवि भाटिया के अनुसार इस समझौते का सबसे अहम परिणाम भारत के निर्यात के लिए बना मौका है। भारत में बनी इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां (जिनकी कीमत 20,000 से 80,000 ब्रिटिश पाउंड के बीच है) ब्रिटेन के मार्केट में छठे साल से बिना शुल्क के बेची जा सकेंगी। निर्यात कोटा धीरे-धीरे बढ़कर 15वें साल तक 88,000 गाड़ियों तक पहुंच जाएगा। इससे वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रहे भारतीय विनिर्माताओं के लिए दीर्घावधि में अहम मौका बनेगा।

भाटिया ने कहा, 'पहले साल में 20,000 गाड़ियों का शुरुआती कोटा भारत के सालाना यात्री वाहन मार्केट का 0.5 प्रतिशत से भी कम है। हालांकि इसका तुरंत वाणिज्यिक असर सीमित है, लेकिन यह समझौता एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के तहत मार्केट तक नपे-तुले तरीके से पहुंच बनाने की अहम मिसाल कायम करता है। इसमें व्यापार उदारीकरण और घरेलू उद्योग के बचाव के बीच संतुलन बनाया गया है।'

समझौते के तहत शुल्क में कटौती एक बार में नहीं बल्कि चरणों में की जाएगी। बड़े इंजन वाली गाड़ियों के लिए ड्यूटी पहले साल में 110 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत हो जाएगी और पांचवें साल तक 10 प्रतिशत पर आ जाएगी। मिड-रेंज गाड़ियों के लिए ड्यूटी 66 प्रतिशत से घटकर 50 प्रतिशत हो जाएगी और इसी अवधि में घटकर 10 प्रतिशत पर आ जाएगी।

उन्होंने कहा, 'आयात कोटा शुरू में 20,000 गाड़ियों से बढ़कर पांचवें साल तक 37,000 हो जाएगा और 15 सालों में कुल 3,78,000 गाड़ियों तक पहुंच मिलेगी। अहम बात यह है कि खास वरीयता दरें (प्रेफरेंशियल टैरिफ) सिर्फ उन्हीं गाड़ियों पर लागू होंगी जो 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (उत्पत्ति के नियम) को पूरा करती हैं और ब्रिटेन में बनी हैं। इसमें दूसरे देशों में बने मॉडल शामिल नहीं होंगे।'

वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने ब्रिटेन से आयात किए जाने वाले वाहनों के शुल्क दर कोटा की निगरानी करने की प्रक्रिया की सार्वजनिक सूचना जारी की है। इस अधिसूचना में सालाना कोटा की संख्या, लागू होने वाली इन-कोटा कस्टम ड्यूटी दरें और कोटा प्रमाणपत्र पाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है।

आईसीसी को खत्म कर देंगे... अमेरिका की खुली धमकी, दुनियाभर के देशों से मांगा साथ

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) के खिलाफ बेहद सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आईसीसी की हर ईंट उखाड़कर खत्म कर देगा। उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों से भी इस अभियान में अमेरिका का साथ देने की अपील की है। ट्रंप प्रशासन का यह अब तक का सबसे आक्रामक रुख माना जा रहा है। मार्को रुबियो ने कहा कि आईसीसी अमेरिका के खिलाफ गोलियों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून के नाम पर युद्ध लड़ रहा है। उनका आरोप है कि यह अदालत अपने अधिकार से बाहर जाकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को निशाना बना रही है।

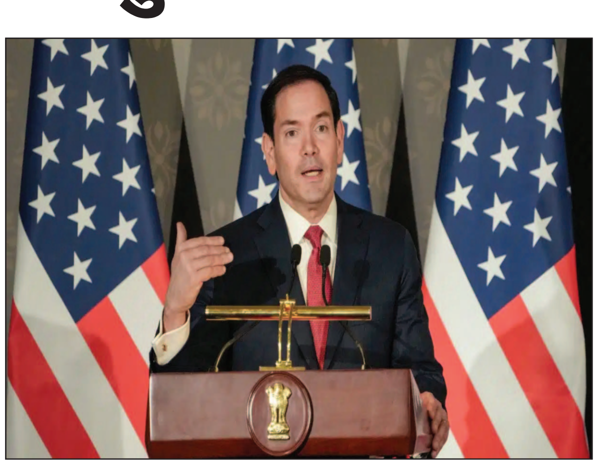

अमेरिका और ICC के बीच विवाद कई साल पुराना है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में आईसीसी ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों पर कथित युद्ध अपराधों की जांच शुरू करने की कोशिश की थी। तभी से अमेरिका इस अदालत का विरोध करता आ रहा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भी अमेरिका ने आईसीसी के कई अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि अदालत अमेरिका और इजरायल से जुड़े मामलों की जांच कर रही थी।

साथ न देने वाले देशों को धमकी

अब अमेरिका ने आईसीसी के खिलाफ और बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी विदेश मंत्रालय पूरी सरकार के साथ मिलकर दुनिया के अलग-अलग देशों से संपर्क कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि दूसरे देश आईसीसी का साथ छोड़ दें और उसके खिलाफ खड़े हों। अमेरिका ने यह भी संकेत दिया है कि जो देश आईसीसी का समर्थन जारी रखेंगे और साथ ही अमेरिका से आर्थिक या दूसरी मदद लेते रहेंगे, उन्हें अमेरिकी जांच और दबाव का सामना करना पड़ सकता है। मार्को रुबियो ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे लेख में कहा कि अमेरिका अपने पास मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने लिखा कि जरूरत पड़ी तो सहयोगी देशों के साथ मिलकर आईसीसी को उसकी ईंट-ईंट उखाड़कर खत्म किया जाएगा।

आईसीसी को कैसे कमजोर करेगा US

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस अभियान में वीजा रद्द करना, यात्रा पर रोक लगाना और आर्थिक प्रतिबंध लगाना जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं। रुबियो, उनके डिप्टी और दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी राजदूत अलग-अलग सरकारों से बात कर रहे हैं ताकि ICC को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग किया जा सके। अमेरिका ICC के सदस्य देशों से अदालत छोड़ने और उसे मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की अपील कर रहा है। जो देश आईसीसीICC के सदस्य नहीं हैं, उनसे भी अमेरिका इस अभियान में साथ देने की मांग कर रहा है।

अपने लेख में रुबियो ने यह भी आरोप लगाया कि आईसीसी पर कुछ वामपंथी गैर-सरकारी संगठन (NGO), वैश्विक समूह और कुछ विकासशील देशों का असर है, जो अमेरिका के खिलाफ काम करते हैं। उन्होंने अल सल्वाडोर में लोगों को भेजने, कथित नार्को-आतंकियों पर अमेरिकी नौसैनिक हमलों और ईरान में अमेरिकी कार्रवाई को लेकर लगाए गए अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के आरोपों को भी खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने माना कि इन मामलों में ICC आगे भी जांच की कोशिश कर सकता है।

सड़क पर तैरती दिखी गाड़ियां, ट्रेन सेवाएं निलंबित, प्रशासन ने जारी किया रेड अलर्ट

बीजिंग, एजेंसी। चीन के उत्तरी हेबेई प्रांत और पूर्वोत्तर लियाओनिंग प्रांत में भीषण बाढ़ के कारण सड़कें जलमग्न हो गईं और गाड़ियां बह गईं। वहीं, लोग आस-पड़ोस की सड़कों पर तैरने, पैडल बोर्डिंग करने और वेक सर्फिंग करने का आनंद लेते दिखे। स्थानीय आधिकारिक मीडिया की ओर से प्रसारित एक निवासी के बयान के अनुसार, हेबेई के कुआनचेंग काउंटी में सड़कों पर जलस्तर दो मीटर से अधिक हो गया। कुआनचेंग में जलमग्न सड़क पर कई कारें आपस में टकराती हुई देखी गईं, जब वे ऊपर-नीचे उछल रही थीं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबित इस साल चीन की मुख्य भूमि से टकराने वाले सबसे शक्तिशाली तूफान, टाइफून बावी के बाद बाढ़ आई।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तूफान जिलिन, लियाओनिंग, हेबेई, शेडोंग, जियांग्सू और अनहुई प्रांतों में मूसलाधार बारिश करेगा, जिससे उन क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा जो पहले की भारी बारिश से पहले ही जलमग्न हो चुके हैं। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, कुआनचेंग में लगभग 1,800 ग्रामीण फंसे हुए हैं। वहीं, अधिकारियों ने कहा कि निवासियों को स्थानांतरित करना और पुनर्स्थापित करना उनकी प्राथमिकता है। लियाओनिंग में, अधिकारियों ने अचानक बाढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक जोखिम की चेतावनी दी है। हेबेई अधिकारियों ने वीचैट पर एक बयान में कहा कि भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी होने के दौरान, सभी प्रकार के काम बंद करने, व्यवसायों को बंद करने और सभाओं को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।

18 साल की युवती का यौन शोषण, कनाडा के मशहूर फैशन डिजाइनर 84 की उम्र में दोषी करार

कनाडा। पीटर नाइगार्ड एक समय में कनाडा के मशहूर फैशन डिजाइनर थे। 18 साल की युवती के यौन शोषण के आरोप में टोरंटो की एक अदालत ने उन्हें 84 साल की उम्र में दोषी ठहराया है। उन्होंने अपनाा जुर्म कबूल कर लिया है। 84 साल के नाइगार्ड सोमवार को ओंटारियो की जेल से वीडियो के जरिए कोर्ट में पेश हुए। फिलहाल वे 11 साल की सजा काट रहे हैं। पीटर को अमेरिका प्रत्यर्पण का डर सता रहा है।

दरअसल, यह मामला 1997-1998 के दौरान का है, जब पीड़ित युवती केवल 18 साल की थी। वह फैशन मॉडल बनना चाहती थी और उसी दौरान नाइगार्ड से मिली थी। 'नाइगार्ड इंटरनेशनल' एक समय में कपड़ों की मशहूर कंपनी थी। पीटर नाइगार्ड उसके फाउंडर थे। नाइगार्ड पर अमेरिका में रैकेटियरिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप भी हैं।

क्यूबेक के सरकारी वकील जेरोम लाफ्लाम ने बताया कि नाइगार्ड की गिल्टी प्ली अचानक से सामने आई। 10 दिन तक चलने वाला ट्रायल पहले से तय था, जिसमें जज सिर्फ फैसला सुनाने वाले थे। मगर नाइगार्ड ने अचानक अपना मन बदल लिया। वकील लाफ्लाम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नाइगार्ड का मन अचानक बदल गया। उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाली महिला गवाही देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अभियोजन पक्ष ने जो सबूत पेश किए, उनसे पता चला कि नाइगार्ड ने मशहूर फैशन डिजाइनर होने का फायदा उठाकर उन महिलाओं को बहलाया-फुसलाया। बचाव पक्ष ने इन सबूतों पर कोई विरोध नहीं किया। सबूतों के मुताबिक, पीड़िता उस समय सिर्फ 18 साल की थी।

बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनते ही नेपाली शेयर बाजार के बुरे दिन आए, मार्च से अब तक 380 पॉइंट की गिरावट

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल में नई सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से लोगों को उम्मीद थी कि वहां के हालात सुधरेंगे, लेकिन अब तक हालात में खास सुधार नहीं हो सका है। नेपाली शेयर बाजार की भी हालत भी बदहाल है। यहां के निवेशकों को उम्मीद थी कि बालेन शाह की अगुवाई वाली नई सरकार बनने से भरोसे का एक नया दौर शुरू होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और पिछले 5 महीने में ही 380 पॉइंट की गिरावट दर्ज हो चुकी है।

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) की अगुवाई वाली सरकार, जिसके पास करीब दो-तिहाई बहुमत है, उससे देश में राजनीतिक स्थिरता, साफ-सुथरी नीतियां और निवेशकों का भरोसा बढ़ने की उम्मीद थी। लेकिन इसके उलट, बाजार उल्टी दिशा में ही चला जा रहा है। मार्च में RSP के सत्ता संभालने के बाद से अगले 106 दिनों में, नेपाल के शेयर बाजार में निराशा ही छाई हुई है।

73 ट्रेडिंग दिनों में 47 दिन की गिरावट

शाह सरकार के कार्यकाल के दौरान 73 ट्रेडिंग दिनों में से, नेपाल स्टॉक एक्सचेंज (Nepse) इंडेक्स 47 दिनों तक गिरा और सिर्फ 26 दिन ही ऊपर चढ़ सका। इस दौरान बाजार में 380 से अधिक अंकों की गिरावट आई। कल सोमवार को, बाजार 2,580 अंकों के सपोर्ट लेवल से भी नीचे चला गया और 2,570।28 अंकों पर बंद हुआ। यह पिछले 6 महीने से अधिक समय में सबसे निचला स्तर है। नेपाली बाजार के जानकारों का कहना है कि इस गिरावट से पता चलता है कि बेचने वालों का पलड़ा भारी है। इससे पहले इंडेक्स पिछली बार 22 दिसंबर, 2025 को इस स्तर से नीचे 2,581.24 अंकों पर बंद हुआ था।

5 महीनों में गिरावट ही गिरावट

बालेंद्र शाह के नेपाल के प्रधानमंत्री बनने से एक दिन पहले, 26 मार्च, 2026 को NEPSE इंडेक्स 2,950।50 पर था। लेकिन सोमवार तक, यह गिरकर 2,570।28 अंकों पर आ गया। इस तरह से गुजरे 5 महीनों में 380 से अधिक अंकों की इस गिरावट से निवेशकों की निराशा की गहराई का पता चलता है। इसी दौरान, शेयर बाजार का कुल आकार करीब 600 अरब रुपये तक घट गया, और इस तरह से निवेशकों की होल्डिंग्स की वैल्यू भी कम हो गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो 26 मार्च को 5।009 ट्रिलियन रुपये था, सोमवार तक गिरकर 4.416 ट्रिलियन रुपये हो गया।

लगातार गिरता जा रहा भरोसा

इस गिरावट की बड़ी वजह शेयर बाजार से जुड़ी घटनाओं की जांच और सरकार के इरादों को लेकर अनिश्चितता के बीच निवेशकों का कमजोर भरोसा माना जा रहा है। सोमवार तक, 79।86 लाख लोगों ने शेयर ट्रेडिंग के लिए अपने डीमैट खाते खोले थे। उनमें से 47 लाख लोगों ने सेकेंडरी मार्केट में ऑनलाइन लेन-देन के लिए ट्रेडिंग मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) खाते खोल रखे हैं। हालांकि, इनमें से महज 4 लाख के आसपास ही एक्टिव निवेशक हैं। नेप्से आम तौर पर उन निवेशकों को एक्टिव निवेशक मानता है जिन्होंने साल में कम से कम एक बार शेयर खरीदे या बेचे हों।

लिस्टेड कंपनियों की संख्या स्थिर

नेपाल में मई के मध्य तक, NEPSE में 294 कंपनियां लिस्टेड थीं, जबकि पिछले साल इसी समय यह संख्या 271 थी। लिस्टेड कंपनियों में से 133 बैंक, फाइनेंशियल संस्थान और इंश्योरेंस कंपनियां हैं। इसके अलावा, 103 हाइड्रोपावर कंपनियां, 28 मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग कंपनियां हैं। साथ ही 9 होटल, 7 इन्वेस्टमेंट कंपनियां, 4 ट्रेडिंग कंपनियां और "अन्य" कैटेगरी में 10 कंपनियां शामिल हैं। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (BFI) और इंश्योरेंस कंपनियां कुल सिक्योरिटीज मार्केट कैपिटलाइजेशन का 50।7 फीसदी हिस्सा रखती हैं।

ईरानी हमले में भारतीय नाविक की मौत पर एमईए सख्त, ईरानी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को किया तलब

नई दिल्ली, एजेंसी। ईरानी हमले में भारतीय नाविक की मौत का मामला गरमा गया है। मंगलवार को भारत ने ईरानी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जवाद हुसैनी को तलब कर जवाब मांगा है। ईरानी अधिकारियों को विदेश मंत्रालय बुलाया गया है। ईरान ने होर्मुज में यूएई के दो ऑयल टैंकरों पर हमला किया था। इस हमले में एक भारतीय चालक दल के सदस्य की मौत हो गई थी जबकि कई घायल हो गए।

यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि उसके 'मोम्बासा' और 'अल बहियाह' टैंकर ओमान की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे थे, तभी उन पर ईरान ने मिसाइलों से हमला कर दिया। इस हमले में 'मोम्बासा' पर सवार चालक दल के एक भारतीय सदस्य की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य लोग घायल गए। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, घायलों में से चार की हालत गंभीर बताई गई है।

भारत ने ईरानी डिप्टी चीफ को किया तलब

यूएई के रक्षा मंत्रालय बताया कि हमले के कारण दोनों टैंकरों में आग लग गई, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा। हालांकि, बाद में आग पर काबू पा लिया गया। यूएई के साथ-साथ भारत ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए नई दिल्ली में ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब कर आधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया है।

जंग के बीच अब तक 11 भारतीयों की गई जान

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच अब तक 11 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। इस संघर्ष के दौरान जहाजों और टैंकरों पर हुए हमलों के बीच कई नाविकों को भी बचाया गया है। पिछले महीने भी तीन भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर 'एमटी सेट्टेबेलो' पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविक मारे गए थे।

अमेरिका-ईरान में फिर से शुरू हुई जंग

बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जंग की शुरुआत हो गई है। अमेरिका ने मंगलवार सुबह ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और यूएई से जुड़े इन दोनों टैंकरों को निशाना बनाकर हमले किए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वाशिंगटन होर्मुज में ईरान की नाकेबंदी फिर से लागू कर रहा है।

'स्टॉप E20 पेट्रोल'... अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया ऑनलाइन सिग्नेचर अभियान, सरकार से की अपील

नई दिल्ली, एजेंसी। E20 पेट्रोल को लेकर बढ़ते विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज "स्टॉप E20 पेट्रोल" ऑनलाइन सिग्नेचर अभियान शुरू कर दिया। पिछले दिनों उन्होंने इसकी घोषणा की थी। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि StopE20petrol।com के जरिए लोग प्रधानमंत्री के नाम याचिका पर हस्ताक्षर कर अपनी आवाज़ दर्ज करा सकते हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार बिना पूरी तैयारी के E20 पेट्रोल देश पर थोप रही है, जबकि लाखों वाहन मालिक माइलेज घटने, इंजन में खराबी और बढ़ते खर्च की शिकायत कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार लोगों की चिंताओं को सुनने के बजाय सब कुछ सामान्य बताने में लगी है।

आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मोदी सरकार लोगों को कोई विकल्प देने को तैयार नहीं है। लोग पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल, E10 और E20 तीनों का विकल्प चाहते हैं, ताकि अपनी जरूरत के हिसाब से ईंधन चुन सकें। लेकिन सरकार इसे भी मानने से इनकार कर रही है।

केजरीवाल ने कहा कि E20 पेट्रोल की ऊर्जा क्षमता कम होने से माइलेज भी कम होता है, फिर भी इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल के बराबर या उससे कम नहीं की जा रही। इससे आम और मध्यम वर्ग पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ गाड़ियों का खर्च बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ईंधन पर भी ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है।

वाहन मालिकों ने माइलेज घटने की शिकायत की

पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल पंपों और सर्विस स्टेशनों पर जाकर लोगों से बातचीत के दौरान भी बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने माइलेज घटने, फ्यूल पंप, इंजेक्टर और इंजन संबंधी समस्याओं की शिकायत की। कई लोगों ने बताया कि पहले के मुकाबले अब गाड़ियों की सर्विस और मरम्मत का खर्च काफी बढ़ गया है।

केजरीवाल ने कहा कि अगर सरकार को E20 लागू करना ही है तो कम से कम लोगों को शुद्ध पेट्रोल और E20 दोनों का विकल्प दिया जाए और E20 की कीमत भी कम की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की परेशानियों को नज़रअंदाज़ कर रही है और उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है।

केजरीवाल ने देशभर के लोगों से की अपील

उन्होंने "स्टॉप E20 पेट्रोल" अभियान में देशभर के लोगों से अपील की है कि वे StopE20petrol।com पर जाकर हस्ताक्षर करें और सरकार से मांग करें कि बिना तैयारी E20 पेट्रोल थोपना बंद किया जाए, लोगों को विकल्प दिया जाए और उनकी चिंताओं का सम्मान किया जाए।

तुम्बाड 2' में आलिया भट्ट की एंट्री, बोलीं- इस दुनिया का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद खास

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म 'तुम्बाड 2' का हिस्सा बन गई हैं। मेकर्स ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। फिल्म में आलिया एक अहम किरदार निभाएंगी। इससे पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फिल्म से जुड़ने का ऐलान किया गया था।

फिल्म 'तुम्बाड 2' में शामिल होने के बाद आलिया भट्ट ने अमर उजाला डिजिटल से खास बातचीत की। फिल्म में अपने किरदार को लेकर भी जानकारी दी। जानिए, फिल्म को लेकर आलिया ने क्या-क्या कहा?

फिल्म से जुड़ने पर आलिया भट्ट ने कहा, 'पहली बार 'तुम्बाड' देखने के बाद से यह फिल्म मेरे जेहन में बसी हुई है। बहुत कम फिल्में ऐसी दुनिया रच पाती हैं, जो आपको पूरी तरह अपने भीतर खींच लें। उससे भी कम फिल्में ऐसी होती हैं, जो रिलीज के कई साल बाद भी लोगों के दिलों और दिमाग में बनी रहती हैं। ऐसे में उस दुनिया का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद खास है।'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं सोहम शाह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। लंबे समय से मैं इन दोनों कलाकारों की प्रशंसक रही हूं और ऐसे किरदार का इंतजार कर रही थी, जो 'तुम्बाड' जैसी रहस्यमयी और यादगार कहानी का हिस्सा हो। मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही हूं, जब दर्शक देखेंगे कि हम सबने मिलकर क्या बनाया है।'

पहली बार साथ दिखेंगे तीनों कलाकार

'तुम्बाड 2' में आलिया भट्ट पहली बार सोहम शाह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। अभिनेता और निर्माता सोहम शाह ने कहा कि आलिया का फिल्म से जुड़ना टीम के लिए खुशी की बात है और दर्शकों को उनका नया अंदाज देखने को मिलेगा। निर्माता डॉ. जयंतीलाल गडा ने बताया कि 'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'आरआरआर' के बाद आलिया के साथ यह उनका तीसरा प्रोजेक्ट है।

3 दिसंबर 2027 को होगी रिलीज

'तुम्बाड 2' का निर्माण सोहम शाह फिल्म्स और पेन स्टूडियोज मिलकर कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन आदेश प्रसाद कर रहे हैं। यह फिल्म 3 दिसंबर 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

2018 में रिलीज हुई थी पहली फिल्म

साल 2018 में रिलीज हुई 'तुम्बाड' को अपनी अलग कहानी और फोकलोर-फैंटेसी शैली के लिए सराहा गया था। रिलीज के बाद फिल्म ने समय के साथ अपनी अलग पहचान बनाई। पिछले साल री-रिलीज के दौरान भी इसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

वेकेशन के बाद मुंबई लौटे ऋतिक रोशन, दोनों बेटों के साथ नजर आईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद

: ऋतिक रोशन हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद और दोनों बेटों के साथ फैमिली आउटिंग पर विदेश गए थे। लेकिन वह अब मुंबई लौट आए हैं।

बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद और अपने दोनों बेटों के साथ छुट्टियां बिताकर मुंबई वापस लौट आए हैं। मंगलवार सुबह उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

ऋतिक रोशन एयरपोर्ट पर काले रंग के कैजुअल कपड़ों, सफेद टी-शर्ट, काली टोपी और स्नीकर्स पहने हुए बेहद सिंपल लुक में नजर आए। इस दौरान ऋतिक के साथ उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद और उनके दोनों बेटे भी थे। सबा के हाथ में सफर का कुछ सामान और तकिया था। सबा का ऋतिक के दोनों बेटों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और वे अक्सर साथ में छुट्टियां मनाने जाते हैं।

ऋतिक रोशन की आगामी फिल्म

ऋतिक रोशन को हाल ही में फिल्म 'अल्फा' में एक कैमियो में देखा गया था। वहीं, सबा आजाद हाल ही में बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' में नजर आई थीं। ऋतिक जल्द ही अपनी फिल्म 'कृष 4' में नजर आएंगे। ऋतिक इस फिल्म में अभिनय के साथ ही इसका निर्देशन भी करेंगे।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित ।
शाखा कार्यालयः S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादकः प्रभात पांडेय सम्पर्कः 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com